सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 246, नई दिल्ली । शनिवार, 16 नवम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

यह मत मानिए कि जीत ही सब कुछ है, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीतना चाहते हैं...

03 गुरपुरब के उपलक्ष पर फेडरेशन की ओर से लंगर का आयोजन
06 डिजिटल युग में साझाकरण
08 लास्ट वर्किंग डे पर सीजेआई चंद्रचूड़ का भावुक विदाई संदेश

दिल्ली मेट्रो के फेज चार कॉरिडोर के लिए पहली ट्रेन पहुंची दिल्ली, डीएमआरसी ने जारी की तस्वीरें

संजय बाटला

दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए पहली मेट्रो ट्रेन दिल्ली पहुंच गई है। इस चरण में कुल पांच कॉरिडोर बनेंगे जिसमें से तीन का निर्माण कार्य चल रहा है। 12.31 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क-मौजपुर मेट्रो कॉरिडोर का 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मार्च तक इस कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू होने की संभावना है। आप भी तस्वीरें देखिए।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस चरण के लिए पहली मेट्रो ट्रेन भी दिल्ली पहुंच गई है। इस चरण में कुल पांच कॉरिडोर बनेंगे, जिसमें से तीन का निर्माण कार्य चल रहा है। 12.31 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क-मौजपुर मेट्रो कॉरिडोर का 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मार्च तक इस कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू होने की संभावना है।

मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत पांच अलग-अलग कॉरिडोर पर 86 किलोमीटर नई लाइन बनेगी। इनमें से जनकपुरी पश्चिम- आरके आश्रम मार्ग, मजलिस पार्क- मौजपुर और एरोसिटी- तुगलकाबाद निर्माणाधीन हैं। अन्य दो नए कॉरिडोर लाजपत नगर-साकेत जी ब्लाक और इंद्रप्रस्थ - इंद्रलोक की टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इस चरण के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने 52 ट्रेन सेट (312 मेट्रो कोच) खरीदने के लिए एल्सटाम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड से समझौता किया है। छह कोच का पहली ट्रेन मुकुंदपुर डिपो में पहुंच गई है। आने वाले दिनों में इसका परीक्षण किया जाएगा।

सभी ट्रेन सेट चालक रहित परिचालन के लिए अनुकूल

डीएमआरसी का कहना है कि 312 कोच में से 144 कोच (24 ट्रेन) मजेंटा लाइन के विस्तारित खंड जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम मार्ग के लिए और 90 कोच (15 ट्रेन) पिंक लाइन के विस्तारित खंड मजलिस पार्क से मौजपुर के लिए आवंटित किए गए हैं। शेष 78 कोच (13 ट्रेन) तुगलकाबाद से दिल्ली एरोसिटी कॉरिडोर के लिए हैं। ये सभी ट्रेन सेट चालक रहित परिचालन के लिए अनुकूल होंगे। इनकी अधिकतम गति 95 किमी प्रति घंटे तक की होगी।

चार, छह और आठ कोच वाली लगभग 350 मेट्रो ट्रेनें

दिल्ली मेट्रो का इस समय 391 किलोमीटर का नेटवर्क (नोएडा-ग्रेटर नोएडा कारिडोर और रैपिड मेट्रो, गुरुग्राम सहित) है। इसके 286 मेट्रो स्टेशन के साथ नेटवर्क पर संचालित होती है। चार, छह और आठ कोच के संयोजन वाली लगभग 350 मेट्रो ट्रेनें चलती हैं। भारत में पहली बार चालक रहित मेट्रो परिचालन दिसंबर 2020 में मजेंटा लाइन पर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर शुरू किया गया था। नवंबर 2021 में पिंक लाइन पर भी चालक रहित सेवा का विस्तार किया गया।

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने CAQM द्वारा पेट्रोल /डीजल की BS 3/4 की हलके वाहनों को प्रदूषण के नाम पर बंद करने का कड़ा विरोध किया

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने गुरु नानक जी पावन पर्व पर CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) द्वारा पेट्रोल /डीजल की BS 3/4 की हलके वाहनों को प्रदूषण के नाम पर बंद करने का कड़ा विरोध किया हैं.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना हैं की केंद्र और दिल्ली सरकारे और इनकी कुछ संस्थाएं प्रदूषण की आड़ में कार बनाने वाली कम्पनियो को फायदा कराने की नीति पर काम कर रहें हैं ऐसा हमको दिखाई दें रहा हैं. और इस बार तो हद ही हों गई हैं क्योंकी आज इतने बड़े सिख धर्म के पावन पर्व पर दिल्ली एनसीआर में डीजल पेट्रोलकी BS 3/4 गाड़ियों को बंद किया गया हैं.

दिल्ली में 70% ट्रांसपोर्टर्स सिख धर्म के हैं. इसकी वजह से सिख धर्म के लोगों को केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ आक्रोश हैं.

ये भी सोचने वाली बात हैं की डीजल के BS 2 ट्रको लाखों की संख्या में दिल्ली एनसीआर में खुलेआम चलने की इज्जाजत हैं लेकिन जापानी डीजल की BS 4 की कारो /टैक्सीयों को बंद कर दिया गया हैं.

संजय सम्राट का कहना हैं की 3 महीने से ट्रांसपोर्ट का काम मंदा था इस महीने से पर्यटको ने दिल्ली में आना शरू किया, हमारे ज्यादातर ट्रांसपोर्टर्स ने पेहले से ही बुकिंग ली हुई हैं अब उनको केन्सिल कैसे करें??

इसके अलावा शादियों का सीजन भी चल रहा हैं और क्लाइंट्स से पैसा एडवांस लें रखा हैं. अब उनको कैसे माना करें.

दिल्ली /केंद्र सरकार चाहे तो कृतिम बारिश करा कर प्रदूषण को खत्म कर सकती हैं.

लेकिन ऐसा ना करके ये ट्रांसपोर्टर्स की रोजी रोटी छीन रहें हैं.

जल्दी ही ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मण्डल पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी और CAQM के चेयरमैन से मिलेंगे.

और अगर फिर भी सरकार या CAQM के अधिकारियो ने हमारी बात नहीं मानी तो केंद्र /दिल्ली और CAQM के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया जाएगा.

इसी महीने नोएडा एयरपोर्ट से शुरू होगा कमर्शियल फ्लाइट का ट्रायल

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तीस नवंबर को कमर्शियल फ्लाइट ट्रायल होगा। इसके लिए महानिदेशालय नागर विमानन 25 नवंबर का स्वीकृति प्रदान करेगा। एक दिन के ट्रायल के आधार पर ही एयरो ड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा।

एयरपोर्ट के रनवे, लैंडिंग सिस्टम व कैलिब्रेशन अप्रूवल के आधार पर केवल कमर्शियल फ्लाइट ट्रायल को एयरोड्रोम लाइसेंस के लिए पर्याप्त बताया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. की ओर से 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक बिना यात्री के ट्रायल का दावा किया गया था।

15 नवंबर से 15 दिसंबर तक ट्रायल प्रस्तावित

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगले साल कमर्शियल सेवा शुरू होंगी। इससे पहले एयरपोर्ट पर जांच प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक ट्रायल प्रस्तावित था। ट्रायल के आंकड़ों से तैयार रिपोर्ट के आधार पर एयरपोर्ट के लिए एयरोड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन होना है।

डीजीसीए से 20 मार्च तक मिलेगा एयरोड्रोम लाइसेंस

लेकिन अब केवल तीस नवंबर को कमर्शियल फ्लाइट की ट्रायल रिपोर्ट के आधार पर ही एयरोड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। निर्धारित समय सारिणी के मुताबिक डीजीसीए से 20 मार्च तक एयरोड्रोम लाइसेंस मिल जाएगा।

इसके साथ ही एयरपोर्ट से कमर्शियल सेवा शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि एयरपोर्ट पर कमर्शियल सेवा शुरू करने के लिए चार प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।

तीस नवंबर को कमर्शियल फ्लाइट का होगा ट्रायल

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे, लैंडिंग सिस्टम व कैलिब्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डीजीसीए ने इसके लिए प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गया है। केवल एयरोड्रोम लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होना शेष है। तीन प्रमाण पत्र मिलने के बाद डीजीसीए ने कमर्शियल फ्लाइट ट्रायल को एयरोड्रोम लाइसेंस के आवेदन के लिए पर्याप्त बताया है।तीस नवंबर को कमर्शियल फ्लाइट ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए डीजीसीए (DGCA) से 25 नवंबर तक स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। कमर्शियल फ्लाइट के सफल ट्रायल के बाद विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. की ओर से एयरोड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा।

30 नवंबर तक के लिए बढ़ी OTS योजना की तारीख

वहीं पर दूसरी ओर यमुना प्राधिकरण ने आठ हजार बकायेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ओटीएस योजना को शुरू किया था। योजना के तहत 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आवेदन करना था, लेकिन योजना में आवेदन कम आने के बाद प्राधिकरण ने इसे पहले इसे 15 नवंबर तक बढ़ाया था। लेकिन अब इसे 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यमुना प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक में एक मुश्त समाधान योजना निकालने का फैसला किया गया था।

दिल्ली में ग्रेप-3 के लागू होने के बाद क्या-क्या हुआ बदलाव? मंत्री गोपाल राय ने दिया ताजा अपडेट

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेप-3 के तहत नियम लागू हो गए हैं। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि प्रदूषण के मद्देनजर 106 बसें शटल सेवा के रूप में चलेंगी मेट्रो ट्रेनें 60 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। GRAP 3 के उपायों के तहत निजी भवन निर्माण विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

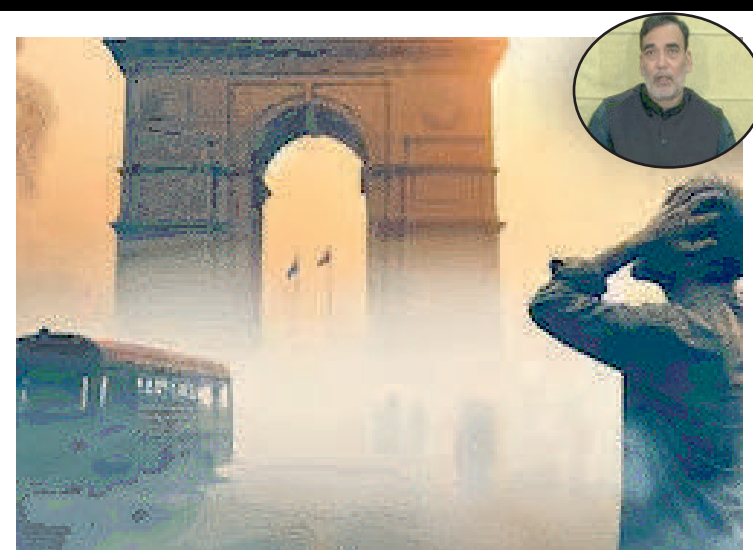

नईदिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेप 3 के तहत नियम लागू हो गए हैं। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि प्रदूषण के मद्देनजर 106 बसें शटल सेवा के रूप में चलेंगी, मेट्रो ट्रेनें 60 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। GRAP 3 के उपायों के तहत निजी भवन निर्माण, विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में वाहन प्रदूषण के कारण PM 2.5 का स्तर उच्च हो गया है। दिल्ली में बीएस III पेट्रोल, बीएस IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ई-बसों, सीएनजी पर चलने वाली बसों को छोड़कर दिल्ली में अन्य ईंधन से चलनेवाली अंतरराज्यीय बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

दो दिनों तक एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-3 के तहत नियम को लागू किए हैं। दरअसल, लगातार दो दिनों तक हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है। शुक्रवार को भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता 411 एक्यूआई के साथ गंभीर श्रेणी में थी। गोपाल राय ने कहा कि ई-बसों और सीएनजी वाहनों को छोड़कर अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हालात नहीं सुधरे तो कृत्रिम बारिश पर विचार

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए मंत्री ने दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त 106 क्लस्टर बस सेवाएं और मेट्रो ट्रेनों द्वारा 60 अतिरिक्त यात्राएं शुरू करने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि अगर हवा की गुणवत्ता और खराब होती है तो कृत्रिम बारिश जैसे आपातकालीन उपायों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में फिर से बात करेंगे।

घर से काम करने का किया आग्रह

उन्होंने कहा कि ग्रेप 3 के उपायों के तहत निजी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राय ने कहा, ₹हम दिल्ली में ग्रेप-3 उपायों को और अधिक प्रभावी बनाने पर काम कर रहे हैं।₹ उन्होंने लोगों से छोटी दूरी की यात्रा के लिए साइकिल का उपयोग करने, सार्वजनिक परिवहन और कारपूल पर भरोसा करने या जब भी संभव हो घर से काम करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि विंटर एक्शन प्लान को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, परिवहन, डीटीसी, मेट्रो, शिक्षा और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक अंतर-विभागीय बैठक आयोजित की गई थी।

सीएम योगी के रोड शो को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

परिवहन विशेष न्यूज

यूपी के गाजियाबाद में शनिवार यानी 16 नवंबर को डायवर्जन रहेगा। सीएम योगी के रोड शो के चलते दोपहर में दो बजे से देर शाम तक रूट डायवर्ट रहेगा। बताया गया कि सीएम योगी उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी के लिए रोड शो करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर किन-किन रूटों पर वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा।

गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा के समर्थन में विजय नगर क्षेत्र में रोड शो करने आएंगे। रोड शो के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए 11 स्थानों पर वाहन पार्किंग भी तय की गई है।

एडीसीपी यातायात पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि डायवर्जन प्लान के मुताबिक ही शनिवार को यातायात संचालित किया जाएगा। डायवर्जन शनिवार दोपहर 12 बजे से देर शाम तक लागू रहेगा।

रोड शो की तैयारी में जुटा प्रशासन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम को विजयनगर इलाके में रोड शो के लिए आएंगे। रोड शो के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारी तेज कर दी है। उत्सव भवन से विजय नगर थाने जाने वाली रोड पर रोड शो के लिए बेरिकेडिंग लगा दी गयी है। इस रोड पर आज और कल यातायात भी बाधित रहेगा।

यह रहेगा डायवर्जन

-मोहननगर से मेरठ तिराहा की ओर आवाजाही बंद रहेगी। ऐसे वाहन मोहननगर से वसुंधरा से डाबर होते हुए यूपी गेट से एनएच-नौ होकर जाएंगे।

-राजनगर एक्सटेंशन चौराहे से मेरठ तिराहा एवं राजनगर एक्सटेंशन की ओर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे वाहन हापुड़ चुंगी से आत्माराम स्टील से एनएच-नौ पर जाएंगे।

-जीटी रोड पर लोहा मंडी के पास साजन मोड़ से चौधरी मोड की ओर भारी वाहन नहीं आएंगे। लाल कुआं से एनएच-नौ होते हुए गंतव्य को जाएंगे।

-विजयनगर टी-पाइंट से विजय नगर की तरफ ऐसे वाहन नहीं जाएंगे। जल निगम टी-पाइंट से मेरठ तिराहा की ओर भी भारी वाहन नहीं जा पाएंगे।

निजी वाहनों के लिए डायवर्जन

-चौधरी मोड़ से रेलवे पुल उतार से उत्सव भवन की तरफ वाहन नहीं जा पाएंगे। ऐसे सभी वाहन रेलवे पुल उतार विजयनगर साइड से सिग्नल कारखाना होकर विजयनगर बाईपास की ओर जा सकेंगे।

-सैन चौक से रेलवे स्टेशन एवं डीएवी चौराहा प्रताप विहार की ओर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

-मेडिकल तिराहा प्रताप विहार से सैन चौक की ओर वाहन नहीं जा पाएंगे।

वाहनों के लिए पार्किंग

-चौधरी मोड से रेलवे ब्रिज होते हुए आने वाले सभी हल्के वाहनों की पार्किंग रेलवे ग्राउण्ड (पी-एक) में की जाएगी-

-लेबर चौक की ओर से आने वाले सभी हल्के वाहनों की पार्किंग रामलीला मैदान (पी-दो) एवं जेकेजी इंटरनेशल स्कूल (पी-तीन) में की जायेगी।

-गऊशाला रोड/ थाना रोड से आने वाले सभी हल्के वाहनों की पार्किंग भीमा भाई पार्क (पी-चार) में की जायेगी।

-जल निगम टी-पाइंट की ओर से संतोष मेडीकल कॉलेज होते हुए आने वाले सभी हल्के वाहनों की पार्किंग न्यू रेनबो स्कूल (पी-छह), डीएवी स्कूल (पी-7), शास्त्री पार्क (पी-10) एवं रामलीला मैदान निकट जीवन ज्योति चौक (पी-11) में की जायेगी।

-सिद्धार्थ विहार से आने वाले सभी हल्के वाहनों की पार्किंग विश्वकर्मा तिराहे से दाहिने मुडकर होल्कर पार्क (पी-आठ) एवं मदरसा नूरानी ग्राउण्ड (पी-नौ) में की जाएगी।

-बसों की पार्किंग आर्मी मैदान (पी-पांच) में की जायेगी। सभी बसें सिद्धार्थविहार-डीपीएस लाल बत्ती से मुड़कर भागीरथ चौक, विश्वकर्मा तिराहा, सम्राट चौक होते हुए आर्मी मैदान में आएंगी।

हेल्पलाइन नंबर

ट्रैफिक हेल्पलाइनयातायात हैल्पलाइन नम्बरः- 9643322904, 0120-2986100

यातायात निरीक्षक, प्रथमः- संतोष कुमार सिंह- 7398000808

यातायात निरीक्षक, मुख्यालयः-संतोष चौहान- 7007847097

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

भारत के इन फेमस कुबेर मंदिरों में एक बार जरूर कर आएं दर्शन, धन संबंधी कभी नहीं होगी दिक्कत

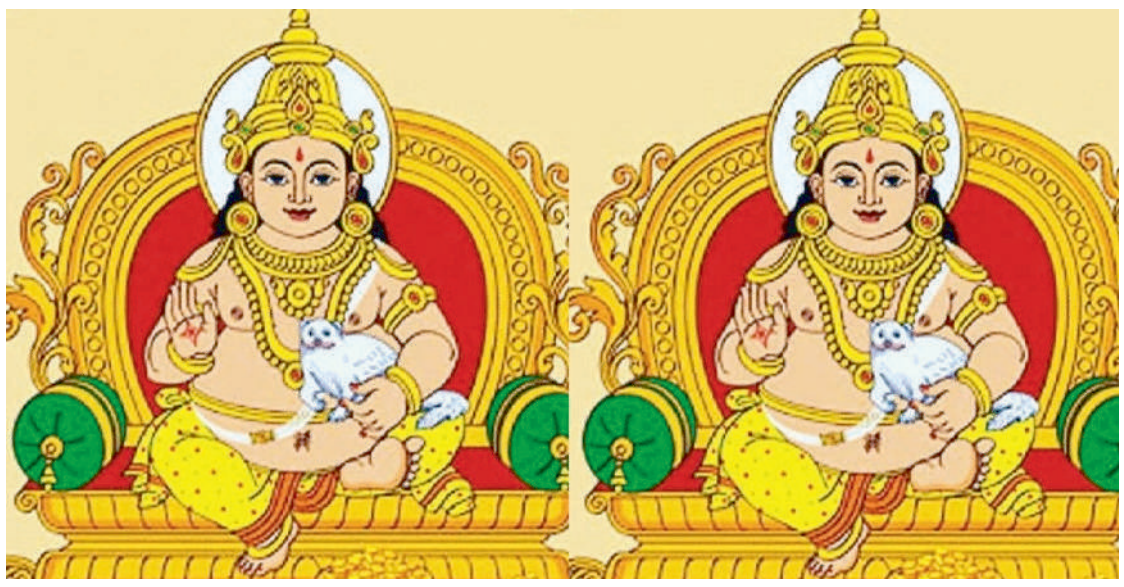

कुछ लोग कुबेर देव का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए भगवान कुबेर के मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको देश के सबसे फेमस कुबेर मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं।

हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। वहीं धन के देवता कुबेर जी को कहा जाता है। लोग धन प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा-अर्चना करते हैं। तो वहीं कुछ लोग कुबेर देव का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए भगवान कुबेर के मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको देश के सबसे फेमस कुबेर मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर दर्शन मात्र से धन की प्राप्ति होती है। अगर आप भी सच्चे मन से कुबेर देव के मंदिर में जाता है। उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। खासतौर पर जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान रहते हैं, तो उनको इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कुबेर देव के इन फेमस मंदिरों के बारे में...

उत्तराखंड का कुबेर मंदिर

उत्तराखंड में कुबेर देव का सबसे प्राचीन मंदिर है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से करीब 40 किमी दूर कुबेर मंदिर है। यह मंदिर जागेश्वर धाम के अंदर आता है। हर साल धनतेरस और दीपावली के मौके पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगती है। बताया जाता है कि इन दोनों दिन जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में आता है, वह खाली हाथ वापस नहीं लौटता है।

गुजरात का कुबेर भंडारी मंदिर

गुजरात के वडोदरा से करीब 60 किमी दूर कुबेर मंदिर काफी ज्यादा फेमस है। बताया जाता है कि यह कुबेर मंदिर करीब 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह मंदिर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। धनतेरस और दीपावली के मौके पर यहां पर भक्तों की भारी भीड़ लगती है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहां आता है, वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है।

खंडवा का कुबेर मंदिर

मध्य प्रदेश में भगवान कुबेर के तीन मंदिर हैं। यह तीनों मंदिर मंदसौर, खंडवा और उज्जैन में हैं। इन तीनों मंदिरों में से सबसे ज्यादा भीड़ खंडवा के कुबेर मंदिर में देखने को मिलता है। जो ओंकारेश्वर में स्थित है। बताया जाता है कि खंडवा के कुबेर मंदिर में दर्शन मात्र से जातक की परेशानियां दूर हो जाती हैं।

सिर्फ भूख नहीं बल्कि इन कारणों से भी उंगली चूसता है बच्चा, जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

नए पेरेंट्स बच्चे की उंगली चूसने का मतलब बच्चे के भूख से लगाते हैं, तो रुक जाइए। क्योंकि सिर्फ भूख लगने पर ही नहीं बल्कि अन्य कई कारणों से भी बच्चे उंगलियां चूसने लगते हैं। तो आइए जानते हैं बच्चे के उंगली चूसने का कारण क्या होता है।

नवजात बच्चे अक्सर अपने मुंह में उंगली डाल लेते हैं। उंगलियां मुंह में चूंसना एक साधारण प्रक्रिया है। जब नवजात बच्चे अपने मुंह में उंगली डालते हैं, तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनको भूख लगी ही और उसको दूध पिलाने लगती हैं। नए पेरेंट्स बच्चे की उंगली चूसने का मतलब बच्चे के भूख से लगाते हैं, तो रुक जाइए। क्योंकि सिर्फ भूख लगने पर ही नहीं बल्कि अन्य कई कारणों से भी बच्चे उंगलियां चूसने लगते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको नवजात शिशु के उंगलियां चूसने के कारण बताने जा रहे हैं।

बच्चे क्यों चूसते हैं उंगली

हर 2-3 महीने के बाद नवजात बच्चे इस दुनिया को समझने के लिए अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। बता दें कि नवजात बच्चे के उंगलियां चूसने के निम्न वजह हो सकते हैं।

स्वाद और बनावट का अनुभव

नवजात बच्चे द्वारा उंगलियों को चूसना और अपने आसपास की चीजों को मुंह में लेना, यह जानने का एक तरीका होता है कि उनके आसपास क्या होता है। यह बच्चे का तरीका होता है उनको उस स्थिति में क्या करना चाहिए। बच्चों का उंगलियां चूसना उनके शारीरिक और मानसिक विकास का हिस्सा है। यह प्रक्रिया उनको चीजों के स्वाद और बनावट का अनुभव कराता है।

दांत निकलना

बता दें कि जब नवजात बच्चा 3-4 महीने का होता है, तो उसके दांत निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे में बच्चे के मसूड़ों में खुजली और दर्द होने लगता है। इस स्थिति में बच्चे उंगली चूसने या चबाने लगते हैं। उंगली चूसने से बच्चे के मसूड़ों पर दबाव पड़ता है और उनको दर्द से राहत मिलती है।

शांति महसूस करना

कई बच्चे मानसिक तौर पर उंगलियां चूसने में काफी शांति महसूस करते हैं। ऐसा तब होता है, जब वह असहज या तनाव महसूस करते हैं। बच्चों द्वारा यह प्रक्रिया उनका भावनात्मक रूप से तनाव कम करने में सक्षम होते हैं।

कहीं भूख तो वजह नहीं

अगर नवजात बच्चा भूख की वजह से उंगलियां चूस रहा है, तो इसके साथ ही होठों को थपथपाना, मुट्ठियों को चूसना और रोने जैसी कई एक साथ काम करने की कोशिश करेगा। अगर आपका बच्चा उंगलियां चूसने के साथ यह सारी हरकतें करता है, तो यह भूख का संकेत है। इसका मतलब है कि उसे दूध पिलाने की जरूरत है।।

बाजारों में मिल रहा है नकली गुड़, कैसे पहचाने असली, सर्दियों में गुड़ खाने के फायदे

सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा गुड़ खरीदा जाता है। जिसके चलते मिलावटखोर गुड़ में मिलावट करने लगते हैं। ऐसे में बाजार में कई मिलावटी गुड़ मिल रहा है। इसकी पहचान कैसे करें आइए आपको बताते हैं। ठंड के मौसम में गुड़ खाने से काफी फायदा मिलता है। अगर आप मिलावटी गुड़ खाएंगे तो यह आपकी सेहत को भी खराब कर देगा। आइए जानते हैं असली गुड़ को कैसे पहचाने?

ठंड की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मार्केट में मिलावटी गुड़ मिल रहा है। सर्दियों के सीजन में गुड़ सेहत के लिए अच्छी होता लेकिन मिलावट से भरपूर गुड़ आपके सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इस मौसम में गुड़ की काफी डिमांड होती है। मिलावटी गुड़ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं असली और नकली गुड़ की पहचान कैसे करें।

नकली गुड़ खाने से क्या प्रॉब्लम्स होती है

मिलावटखोर नकली गुड़ में कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसी चीजें मिलाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से गुड़ का वजन बढ़ाता है। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने में गुड़ के रंग में निखार आता है। आपको बता दें कि गुड़ में चीनी और सेफोलाइट नामक केमिकल की मिलावट की जाती है। यह केमिकल गुड़ की शेल्फ लाइफ बढ़ाती है। मिलावटी गुड़ खाने से पेट दर्द, किडनी स्टोन, स्किन एलर्जी, पाचन संबंधी समस्याएं, विटामिन डी की कमी और हार्ट डिजीज का खतरा बना रहता है।

इस तरह से करें गुड़ की पहचान

- असली गुड़ का रंग गहरा ब्राउन होगा। वही, मिलावटी गुड़ का रंग हल्का ब्राउन, पीला या सफेदी लिए होता है।

- जो गुड़ असली होगा उसका स्वाद मीठा होगा। हालांकि, मिलावटी गुड़ का स्वाद नमकीन, कड़वा या फीका होता है।

- असली गुड़ के छोटे-छोटे टुकड़े पानी में डालें। अगर गुड़ पूरी तरह घुल जाए तो यह असली है। वहीं, आप नकली गुड़ को पानी में डालेंगे तो यह घुलने के बजाय पानी की तली में बैठ जाएगा।

सर्दियों में गुड़ खाने के फायदे

ठंड के मौसम में गुड़ खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं। इम्यून सिस्टम होता है मजबूत। इसके साथ ही एनीमिया का खतरे से भी बचाता है। गुड़ के सेवन से खांसी-जुकाम में आराम मिलता है। डाइजेशन भी बेहतर होता है। गुड़ खाने से शरीर में गर्मी आती है।

प्याज के छिलकों से घर पर बनाएं हेयर ग्रोथ टोनर, सफेद बाल भी हो जाएंगे काले

प्याज के छिलके का हेयर ग्रोथ टोनर यह बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और यह बालों को मजबूत होने के साथ लंबा भी करता है। तो आइए जानते हैं कि आप प्याज के छिलकों से हेयर ग्रोथ टोनर कैसे बनाया जा सकता है।

अक्सर हम फलों और सब्जियों के छिलकों को फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं छिलकों का इस्तेमाल स्किन और बालों के लिए अच्छा माना जाता है। खासकर अगर प्याज के छिलकों की बात की जाए। अनियन ऑयल के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा। लेकिन बता दें कि बालों के लिए प्याज के छिलके भी फायदेमंद होते हैं। प्याज के छिलके से आप हेयर ग्रोथ टोनर बना सकते हैं। यह बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और यह बालों को मजबूत होने के साथ लंबा भी करता है। तो आइए जानते हैं कि आप प्याज के छिलकों से हेयर ग्रोथ टोनर कैसे बनाया जा सकता है।

प्याज के छिलकों के फायदे

प्याज के छिलकों में विटामिन ए, ई और सी पाया जाता है। यह बालों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इससे बालों की लंबाई की बढ़ती है। अगर आपके बालों की ग्रोथ बढ़नी बंद हो गई है, तो आप प्याज के छिलकों से बने टोनर की मदद से आप हेयर ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही यह सफेद बालों को भी रोकता है। ऐसे में आज हम आपको अनियन पील हेयर टोनर बनाने के तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं।

टोनर सामग्री

पानी- 1 गिलास
एलोवेरा- 1 बाउल
प्याज के छिलके- 1 बड़ा बाउल
चावल- 2 बड़े चम्मच
रोज पेटल- 2 कटोरी
गुड़हल- 1 कटोरी
मेथी- 2 चम्मच
रोजमेरी ऑयल- 2-4 बूंद

ऐसे बनाएं हेयर टोनर

सबसे पहले एक पैन में पानी के साथ एलोवेरा, चावल, प्याज के छिलके, गुलाब की पंखुड़िया, मेथी बीज और गुड़हल की पत्तियां डालकर उबाल लें।

अब पानी को धीमी आंच में तब तक उबालें, जब तक पानी का रंग का गाढ़ा न हो जाए।

फिर पानी को एक बोतल में छानकर रख दें।

इसके बाद इस पानी में पानी में रोजमेरी की 2-4 बूंदें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें।

इस तरह से प्याज के छिलकों से बना हेयर ग्रोथ टोनर तैयार कर लें।

इसको आप नहाने से करीब 1 घंटे पहले या फिर रात को सोने से पहले लगा लें।

फिर आप हेयर वॉश कर लें।

गुड़हल के फायदे

बता दें कि गुड़हल के फूल बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। क्योंकि गुड़हल के फूल में एमिनो एसिड पाया जाता है, जोकि केरोटिन बनाता है। यह बालों को शाइन और मजबूती देता है। आप चाहो तो इसको हेयर मास्क की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर पर ही गुड़हल के फूलों का तेल भी बना सकते हैं।

खूबसूरत ट्रेन नजारे की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इन 5 साउथ इंडिया के रेल रुट मजा लें

हम सभी कहीं भी किसी यात्रा पर जाते हैं, तो ट्रेन से जरुर जाते हैं। ट्रेन यात्रा के समय खिड़की वाली सीट होना एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। ट्रेन में बैठे-बैठे खूबसूरत दृश्य देखने का एक अलग ही मजा होता है। अगर आप साउथ इंडिया की ट्रिप पर जा रहे हैं तो इन खूबसूरत ट्रेन रुट्स के बारे में एक बार जरुर जान लें।

प्रत्येक दिन लाखों लोग ट्रेन में सफर जरुर करते हैं। ट्रेन से सफर तय करने का सबसे बेहतरीन साधन है। अगर आपको भी ट्रेन से सफर करना पसंद है तो आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कि साउथ इंडिया की खूबसूरत ट्रेन रुट्स के बारे में, जहां आप भी कर सकते हैं सफर। जब आप इन ट्रेन रुट्स से गुजरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक पल के लिए यहीं ठहर जाएं।

बेंगलुरु से गोकर्ण

कर्नाटक के गोकर्ण सिर्फ वहां के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देश के शिव भक्तों और समुद्र तट के प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं जगह। जब बेंगलुरु से गोकर्ण के लिए सीधी ट्रेन जाती है, तो रास्ते में आपको हरे-भरे कॉफी बागानों और सुंदर पुलों का नजारा देखने को मिलेगा। इस ट्रेन रुट का पूरा रास्ता आपके घने हरे-भरे जंगलों से जाता है। यदि आप इस रुट से यात्रा का प्लान कर रहे हैं, तो कारवार एक्सप्रेस से यात्रा का प्लान बना सकते हैं। यह ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलती है।

वर्कला से कन्याकुमारी

गौरतबल है कि कन्याकुमारी साउथ इंडिया में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। केरल के वर्कला से शुरु होकर कन्याकुमारी तक जाने वाले इस ट्रेन रुट पर प्राकृतिक नजारे से भरे हुए है। इस रुट पर आप ट्रैवल करने के लिए खूब पसंद करेंगे। इस ट्रेन रुट पर सफर करने के दौरान ऐसा लगेगा कि आधे से ज्यादा खूबसूरत वादियों को कवर कर लिया है। आपको बता दें कि आइलैंड एक्सप्रेस वर्कला से कन्याकुमारी तक चलती है। यह ट्रेन करीब 4 घंटों में 127 किलोमीटर की दूरी तय करती है।

मेट्टुपालयम से ऊटी

ऊटी हिल स्टेशन तमिलनाडु का सबसे खूबसूरत है। इस हिल स्टेशन पर कई खूबसूरत ट्रेन रुट्स है, जहां आप प्राकृतिक खूबसूरती देख सकते हैं। यहां पर आप शांत वातावरण के साथ ही हरे-भरे पेड-पौधे देखने को मिलेंगे, जिससे आपको काफी सुकून मिलेगा। आपको बता दें कि, नीलगिरि माउंटेन रेलवे, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में भी शामिल है। वही, मेट्टुपालयम से ऊटी ट्रेन करीब 4.75 घंटों में 46 किलोमीटर की दूरी तय करती है।

पश्चिम बंगाल की खूबसूरती को बढ़ाती हैं ये समुद्र तटीय जगहें, आप भी करें एक्सप्लोर

पश्चिम बंगाल देश का एक ऐसा राज्य है, जो हिमालय पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला है। इसलिए यहां पर हर साल लाखों की संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं।

पश्चिम बंगाल देश का एक प्रमुख और बेहद खूबसूरत राज्य है। यह भारत का चौथा और सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। यह देश का एक ऐसा राज्य है, जो हिमालय पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला है। इसलिए यहां पर हर साल लाखों की संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। पश्चिम बंगाल में सैमसिंग, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, संदक्फू और कलिम्पोंग जैसे हिल स्टेशन्स के बारे में तो हर कोई जानता है।

लेकिन पश्चिम बंगाल में मौजूद खूबसूरत समुद्र तटीय जगहों के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको पश्चिम बंगाल में स्थित समुद्र तटीय जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। जो राज्य की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है। ऐसे में आप भी इन जगहों पर घूमने के लिए पहुंच सकते हैं।

दीघा

अगर पश्चिम बंगाल में किसी शानदार और फेमस समुद्र तटीय जगहों पर घूमने की बात होती है, तो लोग सबसे पहले दीघा पहुंचते हैं। यह जगह कोलकाता से करीब 164 किमी दूर बंगाल के टॉप डेस्टिनेशन में शामिल है।

दीघा बीच को समुद्र की हसीन लहरों के लिए जाना जाता है। यहां पर हर दिन हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। इस बीच की खूबसूरती मुंबई या गोवा बीच से कम नहीं है। यहां पर विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं। इस बीच पर आप सूर्योदय और सुर्यास्त के भी मनमोहक नजारे देख सकते हैं।

शंकरपुर

बंगाल की खाड़ी के पास स्थित शंकरपुर राज्य का छिपा हुआ खजाना माना जाता है। दीघा से करीब 15 किमी की दूरी पर यह खूबसूरत जगह स्थित है।

बता दें कि यह बेहद शांत जगह है, जहां पर आप सुकून के दो पल बिता सकते हैं। यह बंगाल के सबसे साफ-सुथरे बीचेज में से एक माना जाता है। शंकरपुर में एक तरफ समुद्र की लहरें और दूसरी तरफ सफेद रेत देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप यहां पर शानदार और मजेदार वॉटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं।

ताजपुर

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 172 किमी दूर ताजपुर एक बेहद खूबसूरत और फेमस समुद्र तटीय जगह है। यह बेहद खूबसूरत जगह राज्य के मंदारमणि और शंकरपुर के बीच स्थित है।

सैलानियों को ताजपुर बीच सबस ज्यादा आकर्षिक करता है। आप इस बीच से राज्य की खूबसूरती को करीब से निहार सकते हैं। ताजपुर में भारत की सबसे डीप सी बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। आपको यहां का सनसेट और सनराइज का बेहद शानदार नजारा मिस नहीं करना चाहिए।

मंदारमणि

बता दें कि कोलकाता से करीब 171 किमी और दीघा से 30 किमी दूर मंदारमणि गांव स्थित है। यहां पर भारी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। इस गांव में मंदारमणि बीच राज्य के सबसे ट्रेंडी बीच रिट्रीट में से एक माना जाता है। यहां का शांत माहौल और मनमोहक नजारा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां पर आप वॉटर एक्टिविटी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। सर्दियों में घूमने के लिहाज से यह एक बेस्ट जगह है।

एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले सात लाख बच्चों के लिए अच्छी खबर, निगम ने की ये अनोखी पहल

दिल्ली नगर निगम ने अपने विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को खास महसूस कराने के लिए एक अनोखी पहल की है। अब से निगम के स्कूलों में छात्रों का जन्मदिन मनाया जाएगा। 25 नवंबर से शुरू हो रही इस पहल के तहत जन्मदिन वाले छात्र को ताज पहनाया जाएगा और जन्मदिन का सैश दिया जाएगा। साथ ही प्रार्थना सभा में सभी अध्यापक और छात्र जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति ठीक रहे और उन्हें स्कूल आना अच्छा लगे इसके लिए निगम विशेष प्रयोग करने का निर्णय लिया है। इसके तहत एमसीडी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जन्मतिथि मनाई जाएगी।

इसके साथ ही शिक्षकों को भी प्रोत्साहित करने के लिए हर माह निगम 12 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का चयन करेगा। साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र भी देगा। हालांकि सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में उन्हीं का चयन हो सकेगा जिन्हें निगम में पांच वर्ष का अनुभव हो गया है।

दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निगम लगातार स्कूलों को बेहतर करने के लिए कार्य कर रहा है। पुरानी इमारतों के स्थान पर नई इमारतें बनाई जा रही है। साथ ही स्कूलों में बैग फ्री डे समेत अन्य खेल की गतिविधियां भी छात्रों के लिए आयोजित की जाती है।

स्कूलों में प्रार्थना सभाओं में होगा यह कार्य

जिसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित करना। अधिकारी ने कहा कि चूंकि निगम स्कूलों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वह उनके अभिभावक निम्न आय वर्ग के हैं और वह जन्मतिथि मनाने जैसे अवसरों से रह जाते हैं। इसलिए स्कूलों में प्रार्थना सभाओं में यह कार्य किया जाएगा।

इसके लिए सभी स्कूलों को कक्षानुसार बच्चों की जन्मतिथि का कैलेंडेर तैयार करने को कहा गया है। इस कैंलडेर में माह अनुसार जन्मतिथि होगी। ऐसे में जिन दिन जिस विद्यार्थी की जन्मतिथि होगी उस दिन उसको प्रार्थना सभा में जन्मतिथि की शुभकामनाएं दी जाएगी।

साथ ही उन्हें एक ताज के साथ ही जन्मदिन की बधाई वाला पटका भी पहनाया जाएगा। स्कूल की छुट्टी के बाद इसे उतार कर विद्यालय में ही रख लिया जाएगा। इसे फिर दूसरे छात्र के लिए भी उपयोग किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि 25 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरु हो रही है।

स्कूलों में नवाचार करने वाले शिक्षकों को मिलेगा सम्मान

निगम ने हर जोन से एक शिक्षक को हर माह सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के तौर पर सम्मानित किया जाएगा। निगम के अनुसार प्रत्येक जोन से बेस्ट टीचर चुना जाएगा। इसके लिए जोन के उप निदेशक या सहायक निदेशक एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के नाम की सिफारिश करेंगे। इसके लिए शर्तें यह होगी कि शिक्षक के पास 31 अक्टूबर 2024 तक पांच साल का अनुभव हो।

इसके अलावा उपस्थिति छात्रों की उपलब्धियां, प्रशिक्षण, स्कूल के टीम सदस्यों को सहयोग, अनुशासन, अभिभावकों और एसएमसी सदस्यों के साथ समन्वय आदि मापदंड निर्धारित किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में प्रेरणा, अनुशासन, नवाचार, कड़ी मेहनत, बच्चों के साथ सहानुभूति, अतिरिक्त जिम्मेदारी लेना जैसे गुणों को प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षक यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि छात्र कितना सीखते हैं। उन्हें अपना काम अच्छी तरह से करने के लिए समर्थन और प्रेरणा की ज़रूरत होती है। उल्लेखनीय है कि 1500 स्कूल हैं। इनमें सात लाख से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते हैं।

'BJP ने हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश की', दिल्ली के नए मेयर बने महेश कुमार खींची का भाजपा पर हमला

दिल्ली के मेयर महेश खींची ने कहा दलित विरोधी BJP ने अपने LG द्वारा MCD मेयर का चुनाव रोका। बीजेपी नहीं चाहती थी कि कोई दलित व्यक्ति मेयर बने। कल भी बीजेपी ने हमारे पार्षदों को खरीदना चाहा। दिल्ली की जनता ने यह सब देखा और जनता बीजेपी को इसका जवाब देगी। मुझपर अपना विश्वास जताने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं।

नई दिल्ली। दिल्ली के नए मेयर महेश कुमार खींची ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, "दलित विरोधी BJP ने अपने LG द्वारा MCD मेयर का चुनाव रोका। बीजेपी नहीं चाहती थी कि कोई दलित व्यक्ति मेयर बने। कल भी बीजेपी ने हमारे पार्षदों को खरीदना चाहा। दिल्ली की जनता ने यह सब देखा और जनता बीजेपी को इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में देगी। मुझपर अपना विश्वास जताने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, सभी पार्षदों और पार्टी के पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं।"

दिल्ली में अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर LG सक्सेना का एक्शन, अधिकारियों को तत्काल जारी किए ये निर्देश

प्रधान सचिव ने लिखा मुख्य सचिव पहचान के दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस आयुक्त फील्ड स्तर के अधिकारियों को विशेष रूप से सड़क के किनारे और खाली सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों का निरीक्षण करते समय अतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश भी जारी कर सकते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में अचानक वृद्धि के बारे में रिपोर्टों का संज्ञान लिया और तुरंत इसके उपाय सुनिश्चित करने के आदेश दिए। एलजी सक्सेना के प्रमुख सचिव ने मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, आयुक्त एमसीडी और अध्यक्ष एनडीएमसी को इस संबंध में लेटर जारी किया है।

उन्होंने लिखा, "मुख्य सचिव पहचान के दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस आयुक्त फील्ड स्तर के अधिकारियों को विशेष रूप से सड़क के किनारे और खाली सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों का निरीक्षण करते समय अतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश भी जारी कर सकते हैं। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस अवैध अप्रवासियों की पहचान करने के लिए एक महीने तक विशेष अभियान चलाएगी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में आगे की कार्रवाई करेगी।"

पत्र में कहा गया, ₹सड़क, फुटपाथ और पार्कों पर ऐसे लोगों द्वारा अतिक्रमण भी बढ़ रहा है। ऐसी खबरें हैं कि आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि जैसे पहचान दस्तावेज फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार करने और अपनाने के प्रयास चल रहे हैं।₹ उन्होंने आगे कहा कि इन अवैध प्रवासियों द्वारा इन दस्तावेजों को नागरिकता दस्तावेज के रूप में दावा किया जा रहा है।

प्रमाण पत्र देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारण

उन्होंने कहा, "अगर चुनाव पहचान पत्र अवैध अप्रवासियों को जारी किया जाता है, तो यह उन्हें हमारे देश में लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार यानी वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। अवैध अप्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है और ऐसे कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं।"

निरीक्षण करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें

उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए संभागीय आयुक्त के माध्यम से जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर सकते हैं। पत्र में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त फील्ड स्तर के अधिकारियों को सड़क के किनारे और खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों का निरीक्षण करते समय विशेष रूप से अतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश भी जारी कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस एक महीने तक विशेष अभियान चलाए

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एक महीने तक विशेष अभियान चलाएगी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शहर में कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई अनधिकृत कब्जा न हो।

गुरपुरब के उपलक्ष पर फेडरेशन की ओर से लंगर का आयोजन

सुषमा रानी

नई दिल्ली: गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और लंगर का आयोजन किया गया। इसी उपलक्ष्य पर सदर बाजार के व्यापारियों ने कुतुब रोड चौक पर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष राकेश यादव, वाइस चेयरमैन पवन खंडेलवाल, महासचिव सतपाल सिंह मांगा, कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह, उपाध्याय राजकुमार गुप्ता, विष्णु, बरी मार्केट ट्रेडर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र आर्य, कुलदीप सिंह, रमेश सचदेवा, सुनील पुरी सहित अनेक व्यापारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा ने बताया कि हर वर्ष सदर बाजार में बड़ी धूमधाम से गुरपुरब मनाया जाता है जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। इस अवसर पर आए हुए सभी व्यापारियों ने अपील की के गुरु नानक देव जी के बताए हुए मार्ग पर चले जिसमें आपसी भाईचारा बना रहे और फेडरेशन की ओर से सभी व्यापारियों का स्वागत भी किया गया।

"दिल थाम कर देखेंगे फिल्म के एक्शन सींस" ग्लेडिएटर 2

सुषमा रानी

मुझे आज भी याद है जब मैं करीब 24 साल पहले इस फिल्म के पहले पार्ट का रिव्यू करने नजदीकी मल्टीप्लेकस गई थी, हॉल पूरी तरह भरा हुआ था तो अगले दोनो शो भी एडवांस में ही फुल थे, यही नजारा इस बार फिर नजर आया जब पॉल मेस्कल के फैंस अपने चहेते हीरो की फिल्म देखने अपने फ्रेंड फैमिली के साथ सिनेमा आए।

इस फिल्म को देखते हुए मेरे दिल में भी एक बार फिर से खुशी थी कि पिछली फिल्म ग्लेडिएटर की जबरदस्त कामयाबी के बाद मैं फिर से पॉल मेस्कल की फिल्म देखने के साथ ग्लेडिएटर 2 का रिव्यू करने आई हूं।

एक बार फिर इस फिल्म में पॉल ने अपना दमदार अभिनय तो दिखाया ही साथ ही पॉल के दिल थाम कर देखने वाले एक्शन सींस को देख यह यह एक्शन पिछली फिल्म से कहीं ज्यादा है तो फिल्म में एंटरटेनमेंट का भी फुल तड़का है।

करीब 150 मिनट अवधि की इस फिल्म में जॉनर एक्शन और एडवेंचर भी कम नहीं है। इस फिल्म के डॉयरेक्टर रीडली स्कॉट है जिन्होंने पिछले साल आई फिल्म नेपोलियन का निर्देशन किया यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।

स्टोरी प्लॉट

फिल्म की कहानी की बात करें तो यह फिल्म योद्धा मैक्सिमस और उसके बेटे के इर्द-गिर्द घूमती है जिसका नाम लूसीयस है इस फिल्म मेवलूसीयस का किरदार पॉल मेस्कल ने निभाया है बेटा भी अपने पिता की तरह ही एक शक्तिशाली योद्धा है जो रोम के अत्याचारी शासको के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है इस युद्ध में उसकी पत्नी अरिष्ट भी उसका साथ देती है जो खुद भी एक अच्छी योद्धा है। फिल्म में अरिष्ट का किरदार कोनी ने जानदार ढंग से निभाया है। फिल्म की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब लूसीयस लड़ते-लड़ते ग्लेडिएटर का रूप धारण कर लेता है, अब देखना यह है कि लूसीयस रोम के अत्याचारों से वह कैसे लड़ता है और इस युद्ध का क्या परिणाम होता है।

एक नजर में

मेरी नजर में फिल्म केवसभी एक्शन सीक्वेंस कमाल के हैं। फिर चाहे बात करे वारियर योद्धाओं के गेटअप की या फिर खून खराबी की सभी सीन आपकी चौंका देंगे इस फिल्म की सिनेमैटोग्राफी बेहतरीन है, जो पुराने माहौल के युद्ध वातावरण को बखूबी रियलिटी से रूबरू कराता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक गजब है और हर एक सीन में जान डालने का काम करता है।

यह फिल्म पिछली फिल्म से काफी बेहतर है इस बार स्टोरी को ज्यादा डेवलप किया गया है। हालांकि फिल्म थोड़ी लंबी जरूर है पर यह आपका मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती।

ओवर ऑल

अगर आप अच्छी कहानी और जबरदस्त एक्शन के शौकीन है और इस फिल्म का पहला पार्ट देखा है तो इस फिल्म को मिस न करे और अपने फ्रेंड्स फेमिली के साथ इस फिल्म को देखे फिल्म फुल पैसा वसूल है।

भारत में मुसलमान न्याय, संयम और शांति की आवाज़ बनें: अमीर जमाअत-ए- इस्लामी हिन्द

सुषमा रानी

हैदराबाद। यहां के पहाड़ी शरीफ स्थित वादी-ए-हुदा मैदान में आयोजित राष्ट्रीय सदस्य सम्मेलन (इज्तेमा-ए-अर्कान) में 15,000 से अधिक सदस्यों को संबोधित करते हुए जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के अमीर (अध्यक्ष) सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने समाज में न्याय और संयम की आवश्यकता और महत्व पर जोर दिया। आज की वैश्विक नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों और संकटों पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने जमाअत के कैडर और मुस्लिम समुदाय से आगे आने और न्याय और समानता के दीप प्रज्वलित करने का आग्रह किया। सदस्यों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि, ₹शांति और न्यायपूर्ण समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उच्च नैतिक चरित्र की आवश्यकता है। यह सभा हमारे उद्देश्य के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।" सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि ₹यह सम्मेलन अनुभवों को साझा करने, त्याग, अनुशासन, सामूहिक उत्साह और नैतिक शक्ति को सुदृढ़ करने का एक मंच है। इस्लाम और उसकी शिक्षाओं पर व्यापक चर्चा और वाद हमारे लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करती है। हमें इस माहौल का उपयोग जनमत को सही दिशा में आकार देने के लिए करना चाहिए।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि "जब संयम का निश्चित मार्ग त्याग दिया जाता है, तो उग्रवाद उत्पन्न होता है, जिससे अन्याय होता है।" मुसलमानों और अन्य उपेक्षित समुदायों के वर्तमान संकटों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने एकता और लचीलेपन का आग्रह किया और कहा, "यद्यपि ये परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन इनमें सफलता और गौरव के बीज छिपे हैं।₹ अमीर जमाअत ने सदस्यों से उन लोगों से प्रेरणा लेने को कहा, जिन्होंने ₹परिस्थितियों पर विलाप करने या दोषारोपण करने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और अल्लाह ने उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने नवीन समाधान खोजे, नए तरीके अपनाए और नए मील के पत्थर स्थापित किए। उनके अनुभव, सफलता की कहानियाँ और उपलब्धियाँ हम सभी के लिए संपत्ति हैं। इस सभा के माध्यम से यह संपत्ति जमाअत के सदस्यों के दरमियान साझा की जाएगी।"

वैचारिक और संगठनात्मक पहलुओं पर जमाअत के शीर्ष नेतृत्व के वक्तव्यों के अलावा, जमाअत के महासचिव टी आरिफ अली ने संगठन की विगत दस वर्षों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमाअत और उससे संबद्ध संस्थानों द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "आध्यात्मिकता, अंतर-धार्मिक समझ, अनुसंधान और शिक्षा, सामाजिक विकास, शिक्षा, नीतिगत मुद्दे, मूल्य-आधारित राजनीति, न्याय आधारित अर्थव्यवस्था आदि से संबंधित जमाअत के कार्य विभिन्न स्तरों पर समाज को लाभान्वित कर रहे हैं और बदल रहे हैं। विगत दो वर्षों में ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम कर रहे जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द से संबद्ध संस्थानों से 8 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में 130 से अधिक ब्याज मुक्त सूक्ष्म-वित्त पहलों के माध्यम से लाखों परिवारों को सैकड़ों करोड़ रुपये की राशि के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए गए जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया। इसी तरह जमाअत और उससे संबद्ध संस्थाएं धोखाधड़ी के आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हजारों निर्दोष लोगों को बिना जाति-धर्म भेद के कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं।" तीन दिवसीय अखिल भारतीय सदस्य सम्मेलन के पहले दिन कुछ अन्य कार्यक्रम और सत्र सामाजिक कल्याण, शिक्षा और सामुदायिक विकास के मुद्दों पर केंद्रित थे। सम्मेलन परिसर में शुक्रवार की नमाज़ और धर्मोपदेश आयोजित किया गया जिसमें हजारों की संख्या में जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के सदस्य एकत्र हुए और एक स्वर में दुआएं मांगीं। एक विशेष प्रदर्शनी 'इदराक तहरीक शोकेस' में देश भर में सफलतापूर्वक चल रहे 100 से अधिक सामुदायिक और सामाजिक विकास कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया गया।

यीडा 60 गांवों की जमीन पर बसाएगा 'नया आगरा'

यूपी के छह जिलों को लाभ; पढ़ें क्या है मास्टर प्लान 2041

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना प्राधिकरण न्यू आगरा अर्बन सेंटर बनाएगा। इसके लिए एत्मादपुर तहसील के 60 गांवों की जमीन को चिह्नित कर लिया गया है। इसका निर्माण 10 हजार हेक्टेयर में किया जाएगा। पहले फेज में गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर को शामिल किया गया है। जबकि फेज दो में मथुरा अलीगढ़ और हाथरस शामिल हैं।

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने आगरा जिले में अधिसूचित क्षेत्र में न्यू आगरा अर्बन सेंटर का खाका खींच दिया है। एत्मादपुर तहसील के 60 गांवों की जमीन पर न्यू आगरा अर्बन सेंटर को 10 हजार हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा। नियोजन के हिसाब से इसे चार हिस्सों में बांटा गया है।

उसमें उद्योग, पर्यावरण, हेरिटेज व ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। प्राधिकरण ने ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। इसके लिए 15 जनवरी तक वक्त दिया गया है। आपत्ति व सुझावों का निस्तारण करने के बाद मास्टर प्लान को प्रदेश सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

यमुना प्राधिकरण में गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा व आगरा जिले के गांव अधिसूचित है। प्राधिकरण ने फेज एक में गौतमबुद्ध नगर व बुलंदशहर को शामिल किया है। प्राधिकरण का विकास अभी तक फेज एक तक सीमित है।

फेज दो में मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस को शामिल करते हुए मथुरा जिले में राया अर्बन सेंटर व अलीगढ़ जिले में टप्पल अर्बन सेंटर का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। मथुरा में हेरिटेज सिटी व टप्पल में मल्टी माडल लाजिस्टिक हब परियोजना के लिए डीपीआर, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

आगरा जिले के अधिसूचित क्षेत्र में विकास की शुरुआत के लिए प्राधिकरण ने ट्रैक्ट वेल स्काइ ग्रुप से मास्टर प्लान तैयार कराया है। एजेंसी ने आगरा के सामाजिक आर्थिक के साथ संरचनात्मक ढांचे, उद्यमी, पर्यटक, व्यापारी के साथ बैठक कर ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किया है। इसे मास्टर प्लान 2041 का नाम दिया गया है। आगरा में समुचित अधिसूचित क्षेत्र का प्राधिकरण ने मास्टर प्लान तैयार किया है।

चार क्षेत्रों पर फोकस

न्यू आगरा अर्बन सेंटर के मास्टर प्लान में चार क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है। कारोबार के लिए उद्योग, ऐतिहासिक महत्व

को देखते हुए पर्यटन, ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में होने के कारण पर्यवरण, ट्रैफिक व ट्रांसपोर्ट पर खास फोकस किया गया है।

बड़े उद्योग होंगे स्थापित

न्यू आगरा अर्बन सेंटर ताज संरक्षित होने के कारण प्रदूषण रहित इकाइयां ही स्थापित हो सकती हैं। इसलिए प्राधिकरण ने प्रदूषण मुक्त बड़ी औद्योगिक इकाई लगाने की योजना तैयार की है। इसमें सेमीकंडक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल फोन निर्माण, सॉफ्ट टॉय, होम फर्निशिंग, टेक्सटाइल आदि की इकाइयों के लिए भूखंड आवंटित होंगे।

पर्यटन का नया केंद्र बनेगा न्यू आगरा अर्बन सेंटर

आगरा में ताज महल और फतेहपुर सीकरी की ऐतिहासिक इमारतें दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। प्राधिकरण की योजना न्यू आगरा अर्बन सेंटर के जरिये पर्यटन की संभावनाओं को और बढ़ाना है।

इसके तहत देश दुनिया की विभिन्न ऐतिहासिक साइट, हॉलीवुड, बॉलीवुड आदि से संबंधित मॉडल विकसित किए जाएंगे। पर्यटकों के लिए एक ही जगह पर दुनिया भर के समृद्ध इतिहास से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम और राटरडैम की तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा।

थीम पार्क किए जाएंगे विकसित

टीटीजेड में होने के कारण पर्यावरण पर विशेष ध्यान होगा। थीम आधारित पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, पार्क, हरित पट्टी आदि विकसित की जाएंगी। फेज एक व दो की अपेक्षा न्यू आगरा अर्बन सेंटर में हरित क्षेत्र अधिक होगा।

ट्रांसपोर्ट एवं ट्रैफिक की समस्या को हल करेगा न्यू आगरा अर्बन सेंटर

आगरा में बढ़ती यातायात समस्या को न्यू आगरा अर्बन सेंटर में हल किया जाएगा। प्रस्तावित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग हैं। इन पर यातायात के आने वाले समय में बढ़ते दबाव को देखते हुए नए मार्ग, पार्किंग स्थल, ट्रांसपोर्ट नगर आदि विकसित किए जाएंगे। सार्वजनिक परिवहन सेवा के ऐसे विकल्प पर काम होगा, जो यातायात के दबाव को कम करने में मददगार होगा।

न्यू आगरा अर्बन सेंटर का ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। इस पर आपत्ति एवं सुझाव मांगे गए हैं। इनका निस्तारण कर अंतिम मास्टर प्लान तैयार होगा। शासन से स्वीकृति के बाद अर्बन सेंटर के विकास की योजनाएं तैयार की जाएंगी।

डा. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण

विकास की गंगा बहा रही भाजपा सरकार, डिप्टी सीएम ने जनसभा में गिनाए काम; विपक्ष पर बोला तीखा हमला

गाजियाबाद। 2017 से पहले सपा सरकार में प्रदेश के प्रवेश द्वार गाजियाबाद से बॉर्डर के जिलों ललितपुर और देवरिया तक में मिनी मुख्यमंत्री बने होते थे। प्रदेश में गुंडई ,अराजकता, दंगों, जमीनों पर कब्जा करने वालों की, बेटियों की इज्जत लूटने वालों की, व्यापारियों से वसूली करने वालों की सरकार थी। गाजियाबाद का तो और बुरा हाल था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। गाजियाबाद विकसित जिला बन रहा है। बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल सहित मानव जीवन की जितनी भी सहूलियतें हो सकती हैं, उनको आपके वोट की ताकत से भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में देने का काम किया है। यह बातें बृहस्पतिवार को अकबरपुर-बहरामपुर में भाजपा प्रत्याशी संजीश शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा में मतदाताओं को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहीं। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हुए टूटी सड़कें, बुझी हुईं बत्तियां, स्कूल खंडहर, अस्पतालों में डाक्टर नदारद मिलते थे। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से छिन्न भिन्न अव्यवस्था का शिकार था। आज उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पाठक ने कहा कि पूरे देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश अब उत्तर प्रदेश है, छह एक्सप्रेसवे चल रहे हैं। आने वाले दिनों में छह और बनकर तैयार होंगे। कुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। सभी जिलों को फोरलेन से जोड़ने के लिए 2.72 लाख किमी. से अधिक सड़कें बनाकर उत्तर प्रदेश को पूरे राष्ट्र में समृद्धशाली बनाने का कार्य हुआ है।

सपा सरकार में सर्वाधिक 20 हजार मेगावाट बिजली

उन्होंने कहा कि सपा सरकार में सर्वाधिक 20 हजार मेगावाट बिजली और अब 30 हजार मेगावाट से अधिक बिजली उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल हो रही है। पीने के पानी के लिए पहले लोग सरकारी नल लगवाने की बात करते थे, अब जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्य तेज गति से चल रहा है, पानी की दिक्कत नहीं है।

सपा के लोगों ने किया स्कूलों में भूसा भरकर तबेला बनाने का काम

डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा शासनकाल में सरकारी स्कूलों में भूसा भरकर तबेला बनाने का काम सपा के लोगों ने किया था, लेकिन अब कायाकल्प योजना के तहत 95 प्रतिशत से अधिक स्कूलों को मांटेसरी स्कूलों से बेहतर बनाने का काम किया है। बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूता, मोजा, पुस्तकें निशुशल्क मिल रही हैं।

पाठक ने कहा कि सपा के शासनकाल में 1.12 करोड़ बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में थे, अब 1.92 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं। पहले महज 17 मेडिकल कालेज प्रदेश में थे, अब 65 हैं। 17 मेडिकल कालेज और नए प्रारंभ हुए हैं।

'भारत का अपना विकास मॉडल हो, जिसे दुनिया अनुसरण करे', गुरुग्राम के एस.जी.टी यूनिवर्सिटी में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत

गुरुग्राम। जिले के एसजीटी विश्वविद्यालय में भारतीय शिक्षण मंडल के 'विविभा 2024: विजन फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत पहुंचे। मोहन भागवत ने विकास के भारतीय मॉडल की प्रशंसा की है जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर काम करता है। वहीं, उन्होंने विकास के पश्चिमी मॉडल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत को विकास का अपना मॉडल विकसित करना चाहिए जिसका दुनिया अनुसरण कर सके।

उन्होंने कहा, "शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है, लेकिन यह शिक्षा भारत केंद्रित होनी चाहिए। हमें दुनिया भर से अच्छे विचार लेने चाहिए लेकिन कभी भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। यह शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे भारतीय ज्ञान पर आधारित रिसर्च के लिए शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करें।" आरएसएस प्रमुख ने भारतीय शिक्षण मंडल - युवा द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय शोधकर्ता सम्मेलन 'विविभा 2024: विजन फॉर विकसित भारत' के उद्घाटन सत्र में पहुंचे।

अगले 25 वर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण: इसरो प्रमुख

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने पर भारत भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के युवा शोधकर्ताओं को संबोधित किया। डॉ. सोमनाथ ने कहा, "विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अनुसंधान काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उद्योगों, स्टार्टअप, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा कई अन्य क्षेत्रों की क्षमता को बढ़ाता है।" उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

कैलाश सत्यार्थी ने भी रखे अपने विचार

इसरो प्रमुख ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार के बिंदुओं को विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने की जरूरत है। डॉ. सोमनाथ ने इसरो की योजनाओं को रेखांकित करते हुए कहा, "हमने चंद्रमा को छू लिया है और भविष्य में हम मंगल, शुक्र और अन्य ग्रहों पर भी मिशन चलाना चाहते हैं।" कैलाश सत्यार्थी ने इस कार्यक्रम की मेजबानी के लिए आयोजकों की प्रशंसा और धन्यवाद करने के बाद कहा, "यह सम्मेलन एक ऐसे यज्ञ की शुरुआत थी जो पूरी दुनिया को प्रबुद्ध करेगा।"

एन.ओ.सी लेने के बाद भी 551 फ्लैट खरीददारों को नहीं मिला मालिकाना हक, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार

गार्डेनिया एम्स ग्लोरी परियोजना के बिल्डर की मनमानी पर नोएडा प्राधिकरण और शासन-प्रशासन अंकुश लगाने में नाकाम रहे हैं। बिल्डर ने फ्लैट खरीदारों से पूरी रकम वसूल ली लेकिन उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया। परियोजना में फ्लैट की रजिस्ट्री न होने पर 350 फ्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 18 नवंबर को मामले में पहली सुनवाई होगी।

नोएडा। सेक्टर-46 स्थित गार्डेनिया एम्स ग्लोरी परियोजना के गार्डेनिया एम्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर की मनमानी पर प्राधिकरण ही नहीं, बल्कि शासन, प्रशासन तक अंकुश लगा पाने में नाकाम है। बिल्डर ने सोसायटी में रहने वाले 1276 निवासियों ने फ्लैट में कब्जा देने के नाम पर सौ प्रतिशत राशि वसूल ली, लेकिन आज उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया।

जबकि बिल्डर को प्राधिकरण से वर्ष 2019 में 551 फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए अक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी यानी कब्जा प्रमाण पत्र) दिया था, बावजूद एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई। एक वर्ष में रजिस्ट्री नहीं होने पर नियमानुसार प्राधिकरण को ओसी रद करनी पड़ी।

350 फ्लैट खरीदार ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

जब निवासियों को यह पता चला कि बिल्डर मनमानी पर उतारू है तो बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। परियोजना में फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराने पर 350 फ्लैट खरीदार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसकी पहली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

गार्डेनिया एम्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित ने बताया कि तत्कालीन सीईओ रितु माहेश्वरी ने ओसी जारी करने पर शर्त रख दी थी कि रेरा के तहत एस्क्रो अकाउंट खुलवाया जाएगा, जिसमें ओसी के तहत आने वाली राशि का सौ फीसद हिस्सा प्राधिकरण बकाया राशि के लिए लेगा, लेकिन परियोजना के निर्माण पर फाइनेंस करने वाला बैंक के प्राधिकरण की शर्त से सहमत नहीं था।

30 प्रतिशत राशि बैंक के बकाया की वापसी चाहता था। इसी विवाद के चलते फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो सकी, ओसी रद हो गई। वैसे प्राधिकरण के पास 123 फ्लैट मार्गेज है, जिनकी कीमत 400 करोड़ रुपये अधिक है। बकाया को लेकर आकलन गलत किया गया है, जिसे संबंधित अधिकारियों बातचीत की जा रही है। जल्द ही परियोजना का निस्तारण कर दिया जाएगा।

बिल्डर पर प्राधिकरण का 692.48 करोड़ रुपये बकाया

गार्डेनिया एम्स ग्लोरी रेजीडेंट कमेटी सदस्य अनुराग द्विवेदी ने बताया कि परियोजना में 20 टावर है, जिसमें 1586 फ्लैट है, लेकिन एक टावर सील पड़ा है। ओसी मिलने और रद होने की बात बिल्डर ने सोसायटी वासियों से छिपाई। अभी भी बिल्डर मनमानी कर रहा है।

बिल्डर पर प्राधिकरण का 692.48 करोड़ रुपये बकाया है, जिस अमिताभ कांत की रिपोर्ट की सिफारिश को लागू करने के बाद भी बिल्डरों से दो वर्ष कोरोना काल का लाभ देते हुए नोएडा प्राधिकरण कुल बकाया की 25 प्रतिशत 140.53 करोड़ रुपये राशि जमा करने के लिए कहा था, लेकिन आज तक बिल्डर एक रुपया भी प्राधिकरण खाते में जमा नहीं कराया।

जबकि बिल्डर के खिलाफ प्राधिकरण ने भूखंड आवंटन निरस्त करने का सात मई, 27 मई, आठ जुलाई को नोटिस जारी किया। जबकि 28 मई को कुल देयता का बोर्ड भी मुख्य गेट पर लगवा दिया, लेकिन बिल्डर ने तब भी सुध नहीं ली। बिल्डर ने परियोजना में बिना दो तिहाई निवासियों से अनुमति लिए ले आउट प्लान बदवा दिया गया है, जिसमें मार्केट व एक टावर बनाया गया है।

ऐसे में फ्लैट खरीदारों ने बिल्डर से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। नोएडा प्राधिकरण अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने बताया कि बिल्डर पर लगातार बकाया जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है, उसके कुछ फ्लैट सीज किया गया है। बकाया नहीं जमा करने पर निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी।

जनजातीय गौरव को बढ़ावा देने में अग्रणी मध्यप्रदेश

जनजातीय गौरव दिवस पर यह अवश्य याद रखना चाहिए कि अभारतीय ताकतों ने अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के अंतर्गत जनजातीय समुदाय को भ्रमित करने के लिए 9 अगस्त को 'वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे' को 'आदिवासी दिवस' कहकर भारत में बढ़ावा दिया गया।

मध्यप्रदेश वह राज्य है, जिसकी पहल पर देश को 'जनजातीय गौरव दिवस' मिला है। यह बात तो हर कोई मानता है कि मध्यप्रदेश की सरकार ने जनजातीय नायकों का गौरव बढ़ाने के लिए उनसे जुड़े स्मारकों का आगे बढ़कर विकास किया है। राजा शंकरशाह और रघुनाथ शाह, रानी कमलापति, रानी दुर्गावती, टंट्या मामा और भीमा नायक से लेकर कई नायकों के योगदान से लोगों को परिचित कराने के उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मंडला के मेडिकल कॉलेज का नाम बलिदानी हृदयशाह के नाम पर किया गया। वहीं, छिंडवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम 'राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय' किया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'रानी कमलापति रेलवे स्टेशन' किया गया। जबलपुर में 100 करोड़ की लागत से 'रानी दुर्गावती स्मारक' को विकसित किया जा रहा है। जनजातीय गौरव को बढ़ाने के साथ ही जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए भी मध्यप्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। विगत 20 वर्षों में जनजातीय योजनाओं का बजट 1000 प्रतिशत बढ़ा है। मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जहाँ जनजातीय समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पेसा कानून को लागू किया गया है। जनजातीय समुदाय से आनेवाली पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में 15 नवंबर, 2022 को मध्यप्रदेश के 20 जिलों के 89 विकासखंडों को पेसा कानून की सौगात मिली।

मध्यप्रदेश के बजट का अध्ययन करें तो ध्यान आएगा कि 2003-04 में जनजातीय कार्य विभाग का बजट 746.60 करोड़ रुपये था। जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं को बजट की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भाजपा सरकार ने सबसे पहला काम यही किया कि जनजातीय कार्य विभाग के बजट में लगातार बढ़ोतरी की। वर्ष 2003-04 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में जनजातीय कार्य विभाग का बजट 1000 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,768 करोड़ रुपये का हो गया है। इस बजट का उपयोग जनजातीय वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, रोजगार एवं अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं के साथ ही विकास कार्यों को गति देने में किया गया है। विद्यार्थियों को शिक्षा के समुचित अवसर एवं आर्थिक सहयोग के साथ ही सरकार की ओर से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है। कम्प्युटर कौशल सिखाने के साथ जनजातीय युवाओं को पुलिस और सेना में भर्ती का प्रशिक्षण देने का काम भी मध्यप्रदेश में किया जा रहा है। जनजातीय वर्गों के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए आहार अनुदान योजना, सिकल सेल उन्मूलन मिशन, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार ग्राम, देवारण्य, अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम-2020, मिलेट मिशन, प्रधानमंत्री वन-धन योजना, आकांक्षा योजना, प्रतिभा योजना, आवास सहायता योजना, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, प्री एवं पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कोचिंग एवं प्रोत्साहन तथा जनजातीय लोक कलाकृतियों एवं उत्पादों की जीआई टैगिंग जैसे कदम मध्यप्रदेश में उठाए गए हैं।

जनजातीय गौरव दिवस पर यह अवश्य याद रखना चाहिए कि अभारतीय ताकतों ने अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के अंतर्गत जनजातीय समुदाय को भ्रमित करने के लिए 9 अगस्त को 'वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे' को 'आदिवासी दिवस' कहकर भारत में बढ़ावा दिया गया, जबकि इस दिन का भारत और जनजातीय गौरव के साथ कोई संबंध नहीं है। वास्तव में यह तो दुःखद त्रासदी की शुरुआत का दिन है। ब्रिटिस सेना ने अमेरिका के मूल निवासियों का नरसंहार किया। बाद में, उसके अपराध बोध से मुक्त होने के लिए 'वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे' (International Day of the World's Indigenous Peoples) के रूप में 9 अगस्त को चुना गया। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि वैश्विक षड्यंत्र के अंतर्गत ही 'वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे' का अनुवाद 'विश्व आदिवासी दिवस' के रूप में किया गया है। वास्तविकता यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने अब तक 'इंडिजिनियस पीपल' (indigenous people) की स्पष्ट परिभाषा तक नहीं की है। यही कारण है कि जब 1989 में विश्व मजदूर संगठन द्वारा 'राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल' कन्वेन्शन क्रमांक-169 घोषित किया गया, तब उसे विश्व के 189 में से केवल 22 देशों ने ही स्वीकार किया। इसका मुख्य कारण 'इंडिजिनस पीपल' शब्द की परिभाषा को स्पष्ट नहीं करना ही था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने भारत माता के महान बेटे बिरसा मुंडा की जयंती (15 नवंबर) को 'जनजाति गौरव दिवस' के रूप में मान्यता देकर प्रशंसनीय कार्य किया है। जनजाति वर्ग के इस बेटे ने भारत की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक स्वतंत्रता के लिए महान संघर्ष किया और बलिदान दिया। अपनी धरती की रक्षा के लिए उन्होंने विदेशी ताकतों के साथ जिस ढंग से संघर्ष किया, उसके कारण समूचा जनजाति समाज उन्हें अपना भगवान मानने लगा। उन्हें 'धरती आबा' कहा गया। भगवान बिरसा मुंडा न केवल भारतीय जनजाति समुदाय के प्रेरणास्रोत हैं बल्कि उनका व्यक्तित्व सबको गौरव की अनुभूति कराता है। इसलिए उनकी जयंती सही मायने में 'गौरव दिवस' है। जिस प्रकार भगवान बिरसा मुंडा ने विदेशी ताकतों के षड्यंत्रों से भारत को बचाया, उसी प्रकार उनकी स्मृति में मनाया जानेवाला जनजातीय गौरव दिवस भी हमें वर्तमान में चल रही साजिशों से बचाएगा और भारत के 'स्व' की स्थापना की प्रेरणा देगा।

-लोकेन्द्र सिंह राजपूत

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

ईवी पार्ट्स निर्माता वेकमोकॉन ने इकोसिस्टम इंटीग्रिटी फंड के नेतृत्व में जुटाए 10 मिलियन डॉलर

परिवहन विशेष न्यूज

वाहन इंटेलिजेंस कंपनी वेकमोकॉन ने ब्लूम वेंचर्स, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट (बीआईआई) की भागीदारी के साथ इकोसिस्टम इंटीग्रिटी फंड (ईआईएफ) के नेतृत्व में 10 मिलियन डॉलर जुटाए हैं।

कंपनी इस फंडिंग का उपयोग बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए करेगी, जिसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) और बसें शामिल हैं।

इससे पहले, वेकमोकॉन ने 2022 में टाइगर ग्लोबल और ब्लूम वेंचर्स से प्री-सीरीज़ ए राउंड के हिस्से के रूप में 5.2 मिलियन डॉलर जुटाए थे।

कंपनी एक्साइड, बीगॉस, बैटरी स्मार्ट और कई अन्य ग्राहकों के साथ काम कर रही है। वेकमोकॉन ने एम्बेडेड डिज़ाइन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, IoT और डेटा साइंस में सबसे गहरी क्षमताओं में से एक विकसित की है जो अब भारतीय सड़कों पर 70,000 से अधिक वाहनों को शक्ति प्रदान करती है।

वेकमोकॉन टेक्नोलॉजीज के सीईओ पीयूष असाटी ने कहा, "यह नवीनतम फंडिंग राउंड वेकमोकॉन को उच्च-वोल्टेज सिस्टम, ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ESS) में अपने R&D को आगे बढ़ाने, क्षेत्रीय ECU-अनुरूप आर्किटेक्चर विकसित करने, 5G ऑटोमोटिव कनेक्टिविटी समाधानों को आगे बढ़ाने और टीम विस्तार करने में सक्षम बनाएगा। वैश्विक निवेशकों से रणनीतिक समर्थन के साथ, कंपनी वैश्विक बाजार के लिए भारत में विश्व स्तरीय ईवी समाधान बनाने के लिए समर्पित है। पूंजी का एक हिस्सा इलेक्ट्रिक-ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय-मानक आर एण्ड डी बुनियादी ढांचे की स्थापना की दिशा में भी निर्देशित किया जाएगा।"

विस्तार योजनाओं पर बात करते हुए असाती ने कहा कि कंपनी श्रीलंका के बाजार में प्रवेश कर रही है तथा दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीकी बाजारों में अन्वेषण कार्य जारी है।

2016 में आईआईटी दिल्ली में पीयूष असाटी, आदर्शकुमार बलरामन और शिवम वानखेड़े द्वारा स्थापित वेकमोकॉन ईवी के लिए उन्नत कंप्यूटिंग समाधान प्रदान करता है, जिसमें बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस), वाहन इंटेलिजेंस मॉड्यूल (वीआईएम) और ईवी चार्जर शामिल हैं। इसके उत्पाद वर्तमान में भारतीय सड़कों पर 70,000 से अधिक वाहनों को शक्ति प्रदान करते हैं, जो एक्साइड, बीगॉस और बैटरी स्मार्ट जैसे ग्राहकों की सेवा करते हैं।

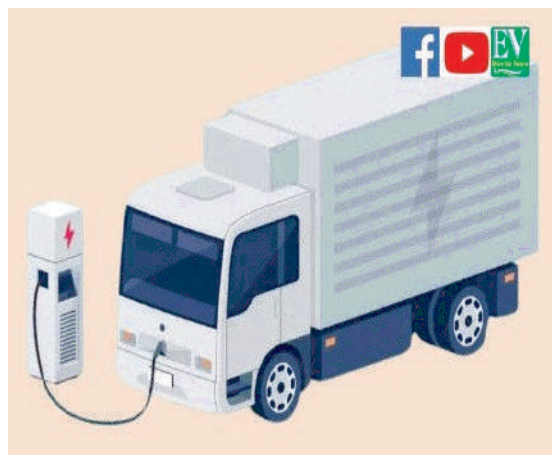

वज्रम इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने बढ़ती वैश्विक ईवी मांग को पूरा करने के लिए विस्तार की बनाई योजना

परिवहन विशेष न्यूज

वज्रम इलेक्ट्रिक लिमिटेड अपनी विस्तार योजना का समर्थन करने के लिए पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी इस धन का उपयोग अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी विनिर्माण सुविधा को उन्नत करने के लिए करना चाहती है।

टिकाऊ गतिशीलता की बढ़ती मांग से प्रेरित ईवी उद्योग की वृद्धि, वज्रम इलेक्ट्रिक के लिए एसर इलेक्ट्रिक और देवू मोटर्स जैसे वैश्विक ब्रांडों के लिए एक प्रमुख विनिर्माण भागीदार के रूप में खुद को स्थापित करने का एक सही समय पर अवसर प्रस्तुत करती है। अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनियाँ अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और ईवी के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तलाश कर रही हैं, जिससे वज्रम इलेक्ट्रिक का विस्तार विशेष रूप से प्रासंगिक हो गया है।

वज्रम इलेक्ट्रिक के सीईओ चंद्र मौली के अनुसार, कंपनी टिकाऊ और कुशल गतिशीलता समाधान प्रदान करके बड़े पैमाने पर ई-मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनना चाहेगी।

भविष्य में वज्रम इलेक्ट्रिक अपने उत्पाद लाइन में विविधता लाने के लिए अपने नए नवाचारों के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रिक ट्राइक्स और ई-साइकिल लॉन्च करेगा। इसके अलावा वज्रम इलेक्ट्रिक अन्य ईवी व्यवसायों को अनुबंध निर्माण सेवाओं के लिए हाथ बढ़ाकर अपनी बाजार पहुंच में विविधता लाने जा रहा है। इससे न केवल वज्रम इलेक्ट्रिक उत्पादों के लिए वैश्विक स्तर पर बाजार का विस्तार होगा बल्कि दुनिया भर के ईवी उद्योग में एक भरोसेमंद विनिर्माण भागीदार के रूप में इसकी स्थिति भी मजबूत होगी।

लॉन्च से पहले होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक की मिली झलक, नए टीजर में दिखे इलेक्ट्रिक मोटर, रियर टायर और लंबी सीट

परिवहन विशेष न्यूज

होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक 27 नवंबर को लॉन्च होने जा रही है। इसके लॉन्च होने से पहले होंडा ने फिर से एक टीजर जारी किया है। जिसमें इसके इलेक्ट्रिक मोटर सीट और हेडलाइट्स की जानकारी देखने के लिए मिली है। इसके साथ ही Honda Activa EV के टायर की भी झलक दिखाई गई है। आइए जानते हैं कि Honda Activa EV किन फीचर्स के साथ आ सकती है।

नईदिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया ने एक नया टीजर जारी किया है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की कुछ झलक दिखाई गई है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 27 नवंबर 2024 को लॉन्च होने जा रही है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम इलेक्ट्रिक एक्टिवा हो सकती है। इसके नए टीजर में इलेक्ट्रिक मोटर, रियर टायर और लंबी सीट डिजाइन के बारे में नई जानकारी के बारे में पता चला है।

Honda Activa EV: क्या नया दिखा

होंडा एक्टिवा ईवी के नए टीजर में एक इलेक्ट्रिक मोटर देखने के लिए मिला है, जिसपर होंडा के लोगों की ब्रांडिंग की गई है। एक्टिवा इलेक्ट्रिक अपने सेगमेंट में मजबूत प्रतियोगी के रूप में स्थापित कर सकता है।

टीजर में लंबी सीट देखने के लिए मिली है। जिससे पता चलता है कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को ही आरामदायक अनुभव मिलेगा। जिसकी वजह से एक्टिवा इलेक्ट्रिक फैमिली और रोजाना कामकाज करने वाले लोगों के लिए काफी उपयोगी बनेगी।

एक्टिवा इलेक्ट्रिक में डुअल स्वैपेबल मोबाइल पावर पैक देखने के लिए मिल सकती है, जिसकी वजह से इसकी रेंज 100 किमी से अधिक हो सकती है। जिसकी वजह से यह शहरी लोगों को काफी पसंद आ सकती है।

इसके पिछले टीजर में एक्टिवा ईवी के एलईडी हेडलाइट्स और कनेक्टिविटी ऑप्शन जैसे ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट और राइडर्स को पास के चार्जिंग स्टेशनों तक मार्गदर्शन करने के लिए बिल्ट-इन नेविगेशन जैसी सुविधाएं देखने के लिए मिली थी। यह तकनीक कनेक्टेड जीवनशैली का एक अभिन्न अंग बन जाती है।

Honda Activa EV: संभावित फीचर्स

होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक में 5 इंच का इंस्ट्रूमेंट कंसोल स्टैण्डर्ड और होंडा रोड सिंक डुओ वेरिएंट में 7 इंच का बड़ा TFT कंसोल देखने के लिए मिल सकता है। बड़े कंसोल में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर देखने के लिए मिल सकता है। इसमें कॉल/एसएमएस अलर्ट, नेविगेशन और म्यूजिक कंट्रोल फीचर्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही USB-C चार्जिंग पोर्ट और तीन राइड मोड स्टैण्डर्ड, स्पोर्ट और इकॉन के साथ ही रिवर्स मोड भी देखने के लिए मिल सकता है।

प्रदूषण कम करने के लिए मंगलुरु में केवल इलेक्ट्रिक वाहन पर आधारित सार्वजनिक परिवहन को दिया जाए बढ़ावा

परिवहन विशेष न्यूज

वायु प्रदूषण और जन स्वास्थ्य पर बढ़ती चिंताओं के बीच मंगलुरु के सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की मांग बढ़ रही है। मंगलुरु स्थित शहरी पर्यावरण एनजीओ, एपीडी फाउंडेशन ने एक अपील में वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे से ईवी में बदलाव को अनिवार्य बनाने का आग्रह किया। मंत्री को लिखे पत्र में एपीडी फाउंडेशन के संस्थापक और सीईओ अब्दुल्ला ए रहमान ने बताया कि मंगलुरु की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के ऑपरेटर शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिवहन उद्योग अत्यधिक कुशल और संगठित है, जो इसे चरणबद्ध तरीके से ईवी में बदलने के लिए उपयुक्त बनाता है। रहमान ने सुझाव दिया कि वित्तीय प्रोत्साहन ईवी निर्माताओं के साथ साझेदारी और पर्यावरण संगठनों के साथ सहयोग इस बदलाव को आसान बना सकते हैं। उन्होंने मंत्री को सार्वजनिक परिवहन में ईवी अपनाने को प्राथमिकता देने के लिए भी प्रोत्साहित किया, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि इलेक्ट्रिक वाहन हानिकारक उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर सकते हैं, वायु गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और शोर के स्तर को कम कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें काफी शांत होती हैं उन्होंने उल्लेख किया कि पत्र की एक प्रति डिप्टी कमिश्नर को सौंपी गई थी।

दक्षिण कन्नड़ सिटी बस एसोसिएशन के दिलराज अल्वा ने कहा कि बुनियादी ढांचे और लागत से जुड़ी चुनौतियों के कारण शहर में ईवी बसें शुरू करने में एक या दो साल और लग सकते हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसें आम तौर पर व्यक्तियों द्वारा सीधे खरीदे जाने के बजाय एग्रीगेटर्स के माध्यम से खरीदी जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चार्जिंग स्टेशन जैसे आवश्यक बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होगी, जो जटिलता को बढ़ाता है। अल्वा ने लागत में अंतर पर प्रकाश डाला और बताया कि जहाँ डीजल बसों की कीमत लगभग 30-40 लाख रुपये है, वहीं ईवी बसों की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। उन्होंने वित्तीय व्यवहार्यता और वित्तपोषण विकल्पों का आकलन करने के महत्व पर जोर दिया। अल्वा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई कंपनियों के साथ चर्चा हुई है, जिसमें मणिपाल में एक बैठक भी शामिल है।

अल्वा ने इस धारणा पर सवाल उठाया कि ईवी पर स्विच करने से प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी, उन्होंने बताया कि ईवी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त नहीं हैं, खासकर बैटरी निपटान के पर्यावरणीय प्रभाव के कारण। उन्होंने टिप्पणी की कि प्रदूषण कम करने के लिए केवल ईवी पर स्विच करना पूर्ण समाधान नहीं है, उन्होंने सवाल उठाया कि बैटरी निपटान के बारे में क्या किया जाएगा।

विनफास्ट ने 2024 में 51,000 से अधिक इकाइयों की बिक्री के साथ वियतनाम के ईवी बाजार में बरकरार रखा अपना नेतृत्व

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अक्टूबर में विनफास्ट ने 11,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन डिलीवर किए हैं, जिससे 2024 के लिए इसकी कुल बिक्री 51,000 से ज़्यादा ईवी हो गई है। इस प्रदर्शन ने अक्टूबर और साल के पहले दस महीनों में विनफास्ट को वियतनाम में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ऑटोमोटिव ब्रांड बना दिया है। कंपनी को घरेलू बाज़ार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने और परिवहन में वियतनाम के हरित परिवर्तन में योगदान देने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है।

अक्टूबर में विनफास्ट ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। 11,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन डिलीवर किए गए, जो पिछले महीने की तुलना में 21% की वृद्धि को दर्शाता है। VF 3 और VF 5 मॉडल सबसे ज़्यादा बिके, जिनकी क्रमशः लगभग 5,000 और 2,600 से ज़्यादा यूनिट बिकीं।

वर्ष की शुरुआत से ही कंपनी ने वियतनाम में 51,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन डिलीवर किए हैं। बड़ी संख्या में प्री-ऑर्डर, उत्पादन क्षमता में विस्तार और डीलरशिप और चार्जिंग स्टेशनों के बढ़ते नेटवर्क के साथ विनफास्ट अपनी अग्रणी बाज़ार हिस्सेदारी बनाए रखने और प्रतिस्पर्धियों से अपने अंतर को और बढ़ाने की स्थिति में है।

अपने घरेलू बाजार में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ऑटोमोटिव ब्रांड बनने की विनफ़ास्ट की उपलब्धि उल्लेखनीय है, क्योंकि यह सिर्फ़ पाँच साल में विदेशी प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में कामयाब रही। इसके अलावा यह बाज़ार का नेतृत्व करने वाला पहला इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड है, जिसने ऑल-इलेक्ट्रिक लाइनअप में बदलाव के दो साल के भीतर गैसोलीन-संचालित वाहनों को पीछे छोड़ दिया।

यह वृद्धि विनफास्ट के पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के लिए उपभोक्ताओं के मजबूत समर्थन को दर्शाती है और उच्च तकनीक क्षेत्र में वियतनाम की क्षमता को उजागर करती है। कंपनी की सफलता वियतनाम को उन कुछ देशों में से एक बनाती है जहाँ एक घरेलू ईवी ब्रांड ऑटोमोटिव बाजार का नेतृत्व करता है।

विनग्रुप के चेयरमैन और विनफास्ट ग्लोबल के सीईओ फाम नहत वुओंग ने विनफास्ट के ग्राहकों के समर्थन को स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी प्रतिक्रिया ने कंपनी के उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उत्पाद की गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि दोनों में निरंतर सुधार के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई।

विनफास्ट वर्तमान में वियतनाम में सात इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल पेश करता है, जिसमें मिनी-एसयूवी से लेकर ई-एसयूवी तक शामिल हैं, जो प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध हैं और जो ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित करते हैं। कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर वैश्विक बदलाव में योगदान देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है।

छोटे व मझोले शहरों में बढ़ेगा CNG का दायरा, 2030 तक खुलेंगे 17,500 सीएनजी स्टेशन

परिवहन विशेष न्यूज

अभी देश में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 7000 के करीब है जिसमें से 80 फीसद महानगरों व बड़ी राजधानियों में है। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक इनकी संख्या 17500 करने का लक्ष्य रखा है। नए खोले जाने वाले स्टेशन ज्यादा गैर-महानगरों में खोले जाएंगे। छोटे व मझोले शहरों में नये सीएनजी स्टेशन सीएनजी वाहनों की बिक्री भी काफी बढ़ा सकती है।

नई दिल्ली। चर्चा तो इलेक्ट्रिक वाहनों की हो रही है, लेकिन जमीन पर रंग सीएनजी का बिखर रहा है। अक्टूबर, 2024 में देश में सीएनजी वाहनों की बिक्री में 67 फीसद का इजाफा हुआ है। वर्ष 2023-24 के पहले छह महीनों की बात करें तो सीएनजी बिक्री में वृद्धि 43 फीसद की है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की कुल बिक्री में सीएनजी वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ कर 33 फीसद, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हुंडई मोटर इंडिया में तकरीबन 15 फीसद हो गई है।

सीएनजी पर लोगों का बढ़ा भरोसा

हाल ही में बजाज आटो ने पहली सीएनजी बाइक लांच की है और कुछ ही दिनों में इसके 10 हजार के करीब बुकिंग हो गई है। यह रफ्तार फिलहार थमती नजर नहीं आ रही है। दैनिक जागरण ने सीएनजी वाहनों के भविष्य को लेकर पेट्रोलियम व नेचुरल गैस रेगुलेटर बोर्ड (पीएनजीआरबी) के चेयरमैन डॉ. अनिल कुमार जैन से लेकर मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर इंडिया के शीर्ष अधिकारियों से बात की और सभी का मानना है कि सीएनजी वाहन अब देश के दूसरे व तीसरे श्रेणी के शहरों में तेजी से विस्तारित होंगे। जब तक देश में बिजली चालित कारों के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ना हो जाए तब तक आम ग्राहकों का भरोसा सीएनजी पर बढ़ता ही रहेगा।

छोटे और मझौले शहरों में बढ़ेगी मांग

सरकारी अधिकारी भी बताते हैं कि सीएनजी का असली गेम अब शुरू होगा, क्योंकि सीएनजी स्टेशनों की संख्या अगले चार से पांच वर्षों में तेजी से छोटे और मझौले शहरों में बढ़ने वाली है। अभी देश में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 7000 के करीब है जिसमें से 80 फीसद महानगरों व बड़ी राजधानियों में है। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक इनकी संख्या 17,500 करने का लक्ष्य रखा है। नए खोले जाने वाले स्टेशन ज्यादा गैर-महानगरों में खोले जाएंगे। छोटे व मझोले शहरों में नये सीएनजी स्टेशन सीएनजी वाहनों की बिक्री भी काफी बढ़ा सकती है। मारुति सुजुकी के एमडी व सीईओ हिसाशी ताकेउची इसके लिए तीन प्रमुख कारण बताते हैं।

सीएनजी के फायदे

- पहला, सीएनजी पेट्रोल व डीजल से काफी सस्ता है।
- दूसरा, सीएनजी वाहनों की माइलेज उक्त दोनों से बेहतर है।
- तीसरा, भारत के बहुत बड़े हिस्से में लोग सीएनजी स्टेशन लगने का इंतजार कर रहे हैं और वह ईंधन आपूर्ति की व्यवस्था होते ही सीएनजी वाहन खरीद करेंगे।

सरकार का क्या है प्लान?

केंद्र सरकार ने अगले कुछ वर्षों में सीएनजी आपूर्ति को बेहतर करने के लिए दो लाख करोड़ रुपये के नये निवेश की योजना तैयार की है। सरकार देश की अर्थव्यवस्था में गैस की मौजूदा हिस्सेदारी 7 फीसद को वर्ष 2030 तक बढ़ा कर 15 फीसद करना चाहती है। पीएम नरेन्द्र मोदी स्वयं कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं। सीएनजी ईंधन को बढ़ावा देना इस योजना का अहम हिस्सा है।

फेस्टिव सीजन में 42.88 लाख वाहनों की हुई खुदरा बिक्री, टू-व्हीलर की बिक्री 14% बढ़ी

नईदिल्ली। इस वर्ष करीब 42 दिन लंबे त्योहारी सीजन के दौरान वाहनों की जमकर खरीदारी हुई है। इस दौरान वाहनों की खुदरा बिक्री में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 12 प्रतिशत की वृद्धि रही है। फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अनुसार, त्योहारी सीजन के दौरान देश में 42,88,248 वाहनों की खुदरा बिक्री हुई है। पिछले वर्ष यह संख्या 38,37,040 थी।

कितनी हुई गाड़ियों की बिक्री

फाडा के प्रेसिडेंट सीएस विग्नेश्वर के अनुसार, इस त्योहारी सीजन में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री सात प्रतिशत बढ़कर 6,03,009 इकाई रही है जो पिछले वर्ष समान अवधि में 5,63,059 इकाई थी। विग्नेश्वर ने कहा कि मांग में वृद्धि और बाजार में उपलब्ध अभूतपूर्व छूट के कारण यात्री वाहनों की बिक्री बढ़ी है। इस सीजन के दौरान दोपहिया की बिक्री 14 प्रतिशत बढ़कर 33,11,325 इकाई रही है। पिछले वर्ष त्योहारी सीजन के दौरान 29,10,141 वाहनों की खुदरा बिक्री हुई थी। दोपहिया की बिक्री मुख्य रूप से मजबूत ग्रामीण मांग के कारण बढ़ी है। इसी तरह, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 1,28,738 इकाई, तिपहिया की बिक्री 1,59,960 इकाई और ट्रैक्टर की बिक्री 85,216 इकाई रही है।

पीवी फेस्टिव व्हीकल रिटेल सेल्स में 7.10% की बढ़ोतरी

भारत में कई वाहन निर्माता पैसेंजर व्हीकल (पीवी) सेगमेंट में भारी फेस्टिव डिस्काउंट दिया, जिसमें 2024 के फेस्टिव पीरियड में रिटेल सेल्स 7.10% बढ़कर 6,03,009 यूनिट पहुंच गई। वहीं, 2023 के इसी 45 दिन की अवधि में 5,63,059 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, जो 39,950 यूनिट्स की बढ़ोतरी हुई।

कमर्शियल व्हीकल (सीवी) सेगमेंट में यह बढ़ोतरी 1.02% की रही। 2024 के फेस्टिव पीरियड में फेस्टिव सेल्स में सिर्फ 1,302 यूनिट्स की ज्यादा बिक्री हुई और यह यह 1,28,738 यूनिट्स हो गई, जबकि 2023 के फेस्टिव पीरियड में 1,27,436 यूनिट्स बिक्री हुई थी। ट्रैक्टर की बिक्री में 1.64% की गिरावट देखने के लिए मिली है।

स्कूल में विज्ञान पुस्तकालय की आवश्यकता और इस के गठन की जरूरत है

विजय गर्ग

विज्ञान पुस्तकालय माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की एक प्रमुख आवश्यकता है। कुछ लोग विद्यालय पुस्तकालय के अस्तित्व की पृष्ठभूमि में विज्ञान पुस्तकालय की स्थापना करने पर प्रश्न उठाते हैं। फिर, प्रत्येक विषय के लिये अलग-अलग पुस्तकालय स्थापित करना वर्तमान आर्थिक स्थिति में व्यावहारिक नहीं लगता। इस प्रकार के तर्क वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। विज्ञान एक ऐसा विषय है जो तथ्यों पर आधारित है। इसमें निरन्तर संवर्द्धन होते रहते हैं। इसके ज्ञान में असीमित गति से वृद्धि हो रही है जिसका मानव जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान प्रत्येक विषय को प्रभावित करता है। पाठ्य-पुस्तकों में विज्ञान शिक्षा के लिये विषय-वस्तु पर्याप्त नहीं है। अनुपूरक पठन सामग्री को खरीदना शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिये आसान नहीं है। किन्तु इनका उपयोग भी शिक्षक-शिक्षार्थी के लिए एक अनिवार्यता है, अन्यथा विज्ञान शिक्षण अपूर्ण रहेगा। विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान की विशिष्ट सभी पुस्तकें, साहित्य और पत्र-पत्रिकायें मँगाकर व्यवस्थित नहीं रखी जा सकतीं। फिर इस पुस्तकालय की अपनी व्यावहारिक समस्यायें होती हैं। एक ही साथ एक विद्यार्थी को एक से अधिक पुस्तकें नहीं दी जा सकतीं। विद्यालय के बजट में भी केवल विज्ञान-विषय के लिए ही अतिरिक्त साहित्य जुटाने के लिए विशेष प्रावधान सम्भव नहीं हैं। ऐसी स्थिति में विज्ञान का अलग पुस्तकालय होना आवश्यक है। इसका प्रबन्ध विज्ञान के शिक्षक और विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त आर्थिक और कार्यभार विद्यालय पर नहीं पड़ता। साथ ही विज्ञान की समस्त पठन सामग्री का अधिकतम उपयोग इस अवस्था में सम्भव है।

आवश्यकता-

(1) अधिक से अधिक विज्ञान की पुस्तकों के अवसर जुटाकर शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए यह ज्ञान के स्रोत उपलब्ध कराता है।

(2) पत्र-पत्रिकाओं और मुद्रित अनुसन्धान लेखों द्वारा विज्ञान विषय में नवीनतम ज्ञान प्राप्त करने का यह एक सरल अभिकरण है।

(3) विज्ञान शिक्षण शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की जानकारी उपलब्ध कराने से शिक्षक के अनुदेशन की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि होने की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं।

(4) इनके द्वारा शिक्षक स्वाध्याय से विज्ञान शिक्षण की नई-नई विधियों, प्रविधियों, कौशलों, आव्यूहों एवं उपक्रमों में अभिविन्यास प्राप्त करता रहता है। उसको आत्म-अभिगम में प्रशिक्षण प्राप्त होने के अवसर उपलब्ध होते हैं।

(5) अवकाश के सदुपयोग के लिए विज्ञान का पाठ्य-पुस्तकालय आदर्श साधन है इसमंम प्रेरणास्पद पुस्तकों के अध्ययन से पाठक को ज्ञान और मनोरंजन दोनों ही प्राप्त होते हैं।

(6) विज्ञान पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के साहित्य के अध्ययन से विद्यार्थियों तथा शिक्षकों में सृजन शक्ति का विकास होता है।

(7) विज्ञान के मनोरंजक साहित्य के अध्ययन से पाठकों में पढ़ने की आदत के विकास की प्रक्रिया को सहायता मिलती है

गठन- प्रत्येक अच्छे विद्यालय में विज्ञान का पुस्तकालय एक प्रमुख आवश्यकता है। सबसे पहले इसके लिए सुविधाजनक कक्ष की आवश्यकता है। वर्तमान साधनों की सीमाओं में यह सरल नहीं है। विद्यालय में इसके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था करना कभी-कभी व्यावहारिक नहीं लगता। यदि ऐसा सम्भव हो तो यह उत्तम स्थिति है। किन्तु, दूसरी स्थिति में जबकि विद्यालय में इसके लिए अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध न हो तो विज्ञान की प्रयोगशाला और शिक्षक कक्ष में विज्ञान पुस्तकालय का संचालन किया जा सकता है। इसमें विज्ञान की पुस्तकों को वर्गीकरण के अनुसार खुले रैकों में रखा जा सकता है। पत्र-पत्रिकाओं के लिए अलग रैकों की व्यवस्था हो। प्रयोगशाला में ही एक कोने पर अध्ययन के लिए प्रयोगशाला की ही मेज का उपयोग किया जा सकता है। किन्तु, इसके प्रभावी और व्यवस्थित संचालन के लिए सभी शिक्षार्थियों में आत्मानुशासन पहली शर्त है। अन्यथा अव्यवस्था एवं गड़बड़ी की सम्भावनायें रहती हैं।

विज्ञान पुस्तकालय की सुचारु व्यवस्था का क्रियाशील दायित्व विद्यार्थियों पर होना चाहिए। विज्ञान के शिक्षक केवल मार्गदर्शक एवं पर्यवेक्षक का कार्य करें। वे देखते रहें कि पुस्तकालय का संचालन सुचारु रूप से चल रहा है। प्रयोगशाला सहायक को व्यवस्थापक की मुख्य भूमिका सौंपी जा सकती है। पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं को हमेशा विद्यार्थियों के जाने के बाद यथास्थान रखने के लिए छात्रों की समिति बनाई जानी चाहिए। प्रत्येक कक्षा का एक विद्यार्थी इस समिति का सदस्य हो। समिति के सदस्यों का चुनाव कक्षा के ही छात्रों द्वारा किया जाये। इस सदस्यता को कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित अवधि के बाद आवश्यकता पड़ने पर बदला जा सकता है। प्रत्येक कक्षा के लिए सुझाव देने हेतु शिक्षकों की सेवायें उपलब्ध हों पत्र-पत्रिकाओं की प्रमुख बातों का प्रयोगशाला के निर्धारित बुलेटिन बोर्ड के उपयोग से प्रचार किया जाना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक छात्र इस ओर आकर्षित होकर लाभान्वित हो स्कें। विद्यालय के मुख्य पुस्तकालय की सेवायें भी यहाँ ली जा सकती हैं। दोनों पुस्तकालयों के को परस्पर प्रतिस्पर्धा में नहीं होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही विद्यालय के अधिकर्ता कल्याण का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। शिक्षकों, पुस्तकालय अधीक्षक, प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं विद्यार्थीगण सभी के पारस्परिक सहयोग से यह व्यवस्था सफल हो सकती है। विद्यालय प्रशासन को इस लाभप्रद व्यवस्था में अपेक्षित सहयोग और सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

(2) विज्ञान पुस्तकालय के लिए पठन सामग्रियां :

विज्ञान पुस्तकालय के लिए पठन सामग्री का वर्गीकरण निम्नांकित के अनुसार किया जा सकता है-

(1) पाठ्य-पुस्तकें

(2) अनुपूरक और प्रेरणास्पद पुस्तकें

(3) पृष्ठभूमि पुस्तकें

(4) सन्दर्भ पुस्तकें

(5) विज्ञान और भौतिकी की पत्र-पत्रिकायें

(6) विज्ञान एवं भौतिकी का शिक्षा-शास्त्र

माध्यमिक स्तर के लिए विज्ञान पुस्तकालय हेतु उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार हमारे देश में उपलब्ध हिन्दी और अंग्रेजी की प्रमुख पठन सामग्रियाँ यहाँ दी जा रही हैं-

(1) पाठ्य-पुस्तकें- प्रत्येक कक्षा के लिए एक से अधिक पाठ्यपुस्तकें अलग-अलग लेखकों द्वारा निर्धारित होती हैं। आय-व्यय के अनुसार उपयुक्त संख्या में सभी लेखकों की पाठ्य-पुस्तकें पुस्तकालय में होनी चाहिए। सभी पड़ोसी राज्यों में प्रचलित पाठ्यपुस्तकें भी यहाँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(2) अनुपूरक और प्रेरणात्मक पुस्तकें- इस वर्ग में वह साहित्य आता है जिसके अध्ययन से विद्यार्थियों का मनोरंजन हो। इस वर्ग में रोमांचकारी कृतियाँ अध्ययन के प्रति छात्रों को आकर्षित करने का सशक्त साधन है। इनसे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की जिज्ञासा भी शान्त और अभिप्रेरित होती है।

(3) पृष्ठभूमि पुस्तकें- ऐसी पुस्तकों को, जो कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में विकास और प्रगति की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करती है, पुस्तकालय में अवश्य स्थान दिया जाना चाहिए, जैसे-चन्द्रमा की कहानी, पृथ्वी की कहानी, भाप-इन्जन की कहानी, पेन्सलीन की कहानी, मानव मशीन, विज्ञान का दर्शन, वेदों में विज्ञान आदि।

(4) सन्दर्भ पुस्तकें- कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें विज्ञान का व्यापक विवरण है। विज्ञान के किसी भी क्षेत्र की वाछित जानकारी इनसे प्राप्त होती है, जैसे-विज्ञान का पारितोषिक शब्दकोश, विज्ञान का कोश आदि।

(5) विज्ञान एवं भौतिकी की पत्र-पत्रिकायें- इस सम्बन्ध में आगे अनुच्छेद 10.9 में विवरण दिया जा रहा है।

(6) भौतिकी का शिक्षाशास्त्र- विज्ञान-शिक्षण में निरन्तर परिवर्तन हो रहे हैं। शिक्षा में प्रविधि के प्रवेश से एक क्रान्ति आ गयी है। नवाचार विज्ञान के शिक्षा शास्त्र की नियति बन चुकी है। अतः प्रत्येक विज्ञान पुस्तकालय में विज्ञान शिक्षण से सम्बन्धित पुस्तकें अवश्य होनी चाहिए जिससे कि शिक्षक अपनी अनुदेशन क्षमता बढ़ाने में सक्रिय रह सकें। कुछ प्रमुख पुस्तकों की सूची यहाँ भी दी जा रही है। इनमें विज्ञान शिक्षण की प्रचलित सामान्य पुस्तकें शामिल नहीं की गई हैं।

विज्ञान/भौतिकी की पत्र-पत्रिकायें :

भौतिकी के सफल शिक्षण के लिए उसकी नवीनतम खोजों की जानकारी रखना शिक्षक के लिए आवश्यक है। वर्तमान वैज्ञानिक और तकनीकी युग में यह एक मूल आवश्यकता है। उपलब्ध मुद्रित पुस्तकों से ये जानकारियाँ प्राप्त नहीं हो सकती हैं। इसके लिए हमें विज्ञान की पत्र-पत्रिकाओं से ही विज्ञान एवं भौतिकी में हो रहे नवाचार की नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। इसके साथ ही इनसे पाठकों को भौतिकी के क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य करने की अभिप्रेरणा भी मिलती है। भौतिकी शिक्षक अपने शिक्षण अनुभवों का लाभ इनके माध्यम से दूसरों तक पहुँचाने के अवसर प्राप्त करता है तथा स्वयं भी दूसरों के अनुभवों का लाभ उठाकर अपने शिक्षण कार्य को अधिकाधिक प्रभावी बनाने की दिशा में निरन्तर क्रियाशील रहता है इनके माध्यम से देश के कोने-कोने में भौतिकी एवं विज्ञान के शिक्षकों में परस्पर अन्तक्रिया के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे देश में विभिन्न भागों के विज्ञान शिक्षकों में सम्पर्क बना रहता है

शिक्षक के ज्ञान से शिक्षार्थी के अधिगम की ही प्रोन्नति होती है। इन पत्र-पत्रिकाओं के अध्ययन से शिक्षार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास तो होता ही है, वे अपने ज्ञान का विस्तार भी करते हैं। इसलिए प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान पुस्तकालय में अधिक से अधिक पत्र-पत्रिकायें उपलब्ध करानी चाहिए। यहाँ कुछ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं की सूची दी जा रही है। इन्हें पुस्तकालय में उपलब्ध कराया जा सकता।

संपादक की कलम से

डिजिटल युग में साझाकरण

केवल जागरूकता और सक्रिय विकल्पों के साथ, माता-पिता एक सकारात्मक डिजिटल अनुभव बना सकते हैं

डिजिटल युग में, सोशल मीडिया रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो लोगों को दूर-दूर तक जुड़ने, साझा करने और संचार करने की अनुमति देता है। हाल ही में, एक अध्ययन में, यह अनुमान लगाया गया था कि 90 प्रतिशत से अधिक अमेरिकी बच्चे 2 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते सोशल मीडिया पर मौजूद हो जाते हैं। आज, कई माता-पिता अपने बच्चों की उपलब्धियों और उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं और चाहते हैं इन पलों को दोस्तों और परिवार के साथ मनाने के लिए। उनका मानना है कि सोशल मीडिया अपडेट साझा करने और सहायक प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक आसान, त्वरित तरीका प्रदान करता है।

माता-पिता द्वारा सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के बारे में तस्वीरें, वीडियो और विवरण साझा करने की इस प्रथा को 'शेयरिंग' कहा जाता है और यह शहर में चर्चा का विषय बन रही है। इस अभ्यास में बच्चे की तस्वीरें, मील के पत्थर, पारिवारिक गतिविधियाँ, हास्य घटनाएँ और व्यक्तिगत उपलब्धियाँ शामिल हो सकती हैं। साझाकरण अक्सर गर्भावस्था की घोषणा के साथ ही शुरू हो जाता है और बच्चे के विकास, स्कूल की घटनाओं और कभी-कभी किशोरावस्था तक भी जारी रहता है।

साझा करने का अभ्यास भौतिक दूरी को पाटने और भूगोल द्वारा अलग किए गए परिवारों के लिए पारिवारिक बंधन बनाकर और विस्तारित परिवार के सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखकर परिवार के सदस्यों को बच्चे के जीवन में लाने के कई तरीके प्रदान करता है; ऑनलाइन सहायता समुदायों का निर्माण करना जहां साझा करने से समान चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य माता-पिता से सौहार्द और मार्गदर्शन मिल सकता है और यादें संरक्षित हो सकती हैं जिन्हें बाद में माता-पिता और संभावित रूप से बच्चे दोनों द्वारा दोबारा देखा जा सकता है लेकिन इसके विपरीत, साझा करने को काफी आलोचना का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से गोपनीयता, सहमति और नैतिक मुद्दे. अध्ययनों से पता चलता है कि जिन बच्चों को पता चलता है कि उनके जीवन को उनकी सहमति के बिना सार्वजनिक रूप से प्रलेखित किया गया है, वे अपने माता-पिता के साथ विश्वास की समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत कहानियों पर नियंत्रण खोने का अनुभव कर सकते हैं।

जैसे-जैसे बच्चे डिजिटल दुनिया में बड़े होते हैं, छोटी उम्र से ही दस्तावेज़ीकृत ऑनलाइन उपस्थिति उनकी आत्म-धारणा, सामाजिक विकास और रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। व्यापक दर्शकों के संपर्क में आने से यह संभावना बढ़ सकती है कि बच्चों में इस बात को लेकर शर्म या असुरक्षा की भावना विकसित हो जाए कि उन्हें ऑनलाइन कैसे चित्रित किया जाता है।

'शेयरिंग' शब्द एक दोधारी तलवार है, जो कनेक्शन और मेमोरी संरक्षण के रूप में लाभ प्रदान करता है लेकिन महत्वपूर्ण नैतिक और गोपनीयता निहितार्थ रखता है। माता-पिता के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे संतुलन बनाए रखें और जब संभव हो तो अपने बच्चे से सहमति लेने जैसी जिम्मेदार साझाकरण प्रथाओं को अपनाएं; पूरा नाम, स्कूल, स्थान आदि जैसी संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचें और समय-समय पर पुराने पोस्ट की समीक्षा करें और उन्हें हटा दें, जिससे उनके बच्चे के डिजिटल पदचिह्न में कमी आएगी और जैसे-जैसे वे बड़े होंगे, वे अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे।

सुपर ह्यूमन मशीनों के हाथों में न जाए शिक्षा की बागडोर

विजय गर्ग

हाल-फिलहाल की कोई भी तकनीक इतनी उत्तेजना पैदा नहीं कर सकी है, जितनी जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने पैदा की है। यह कल्पना की जा सकती है कि एआई में इस तरह के आश्चर्यजनक विकास के लिए जिम्मेदार लोग इसके भविष्य को लेकर सही ही कहते रहे हैं कि जल्द ही यह इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगी। हमें यह अनुमान भी मान लेना चाहिए कि यह 'बुद्धिमत्ता' उन व्यवहारों और कार्यों को सक्षम बनाएगी, जो उन इंसानी क्षमताओं का नतीजा होती हैं, जिनको हम मूलतः मानवीय मानते हैं और उसी आधार पर फैसले लेते हैं। इसे हम सुपर ह्यूमन एआई (एसएचएआई) कह सकते हैं। मगर सवाल है कि शिक्षा में इसकी मदद किस तरह ली जा सकती है?

ऐसे सुपर ह्यूमन रोबोट शिक्षा में चार प्रकार की भूमिकाएं निभा सकते हैं- छात्र - सहायक के रूप में, शिक्षक - सहायक के रूप में, छात्रों के लिए शिक्षक के रूप में और शिक्षा प्रबंधन संबंधी कार्यों में सहायक के रूप में (इस पर हम यहां बात नहीं करेंगे)। सुपर ह्यूमन तक पहुंचने से पहले ही एआई का शिक्षा में अत्यंत सावधानी से इस्तेमाल होना चाहिए। नीति यही होनी चाहिए- शिक्षा में इसका इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में हो और ऐसा तभी किया जाए, जब सुनिश्चित हो जाए कि इससे कोई खतरा नहीं है। चार परस्पर जुड़े कारणों की वजह से हमें यह नीति बनानी चाहिए। पहला कारण है, खोखला करना। अगर सुपर ह्यूमन एआई सहायक होगी, तो न शिक्षकों को और न ही छात्रों को सोचने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप किसी क्षमता का उपयोग करना बंद कर देते हैं, तो उसको खो देते हैं या वह विकसित नहीं हो पाती। चूंकि, सुपर ह्यूमन एआई में इंसानों जैसी सोचने की क्षमता होगी, इसलिए इसके आने से ज्ञान संबंधी खोखलापन निश्चित तौर पर दिखेगा। हालांकि, लगभग सभी मानवीय क्षमताओं को लेकर यह डर बना रहेगा।

दूसरा, फॉर्म फैक्टर। यह एक तकनीकी शब्द है। इसका मतलब है कि किसी को कोई चीज किस भौतिक रूप में चाहिए- बक्सानुमा, छोटा, मुलायम या अन्य रूपों में। फोन के जरिये हमसे बातचीत करने वाले एआई का फॉर्म फैक्टर एआई रोबोट से अलग होता है, जो हमें मार भी सकता है। शिक्षा से जुड़ी हमारी इच्छाएं और सीखने की मानवीय प्रक्रियाएं कुछ ऐसी होती हैं कि फोन या कंप्यूटर वाले फॉर्म फैक्टर शिक्षा में सुपर ह्यूमन एआई का इस्तेमाल सीमित कर देंगे, क्योंकि प्रभावी शिक्षा के लिए छात्र की शारीरिक व मानसिक दशा को समझना, उसका ध्यान आकर्षित करना आदि आवश्यक होता है और ऐसा बच्चों के समूह में किया जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वे सामाजिक बनें। इन सबका मतलब है कि सुपर ह्यूमन एआई को मौजूदा कक्षा जैसे किसी परिवेश में काम करना होगा। कप्यूटर बॉक्स या स्क्रीन के अंदर फंसे सुपर ह्यूमन एआई की अपनी सीमाएं होंगी।

तीसरा है, नियंत्रण। यदि सुपर- ह्यूमन एआई वाकई उसी रूप में हो, जैसा हम सोच रहे हैं, तो क्या हम इसे अपने निजी और सामूहिक जीवन पर नियंत्रण करने की अनुमति देना पसंद करेंगे? निस्संदेह, सुपर ह्यूमन एआई नियंत्रण करना चाहेगा, चाहे शिक्षक के रूप में या सहायक के रूप में। क्या हमें इस रूप में आगे बढ़ाना चाहिए? याद रखिए, जो शिक्षा को नियंत्रित करता है, वह हमें भी काबू में करता है। चौथा है, विस्तार। यह सबसे मौजूं वजह है। प्रौद्योगिकी मानवीय व्यसनों व विकृतियों को बढ़ाती है। यह असमानताओं को मजबूत बनाती है। इसमें सबसे अच्छी व उपयोगी चीजें हमेशा अमीरों के हाथों में होती है, जबकि गरीबों को सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका प्रतीकात्मक लाभ मिलता है।

शिक्षा में एआई का कोई भी लाभ अलग-अलग तरह से अमीरों के हिस्से में जाएगा, फिर चाहे वह व्यक्ति के तौर पर हो या राष्ट्र के तौर पर और इसका प्रतिकूल नतीजा सबसे पहले व सामान्य तौर पर वंचितों को ही भुगतना होगा, जिसके बाद पूरी मानवता को क्या हम शिक्षा को ऐसी किसी तकनीक के हवाले कर देना चाहते हैं, जो भले इंसानों जैसी लगे, लेकिन इंसान न हो और अधिक ताकतवर हो; जो छात्रों के दिमाग को खोखला कर दे और हमें नियंत्रित करने की स्थिति में हो; जो असमानता व संघर्ष को बढ़ा दे ? इनका जवाब हमें पता ही है।

भारत के युवाओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। यहां बताया गया है कि कौशल अंतर से सीधे कैसे निपटा जाए

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की रिपोर्ट भारत के कार्यबल में कौशल अंतर को संबोधित करने और पाटने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह दर्शाता है कि प्रति वर्ष कार्यबल में शामिल होने वाले 13 मिलियन लोगों में से केवल एक-चौथाई प्रबंधन पेशेवर, एक-पांचवां इंजीनियर और एक-दसवां स्नातक ही रोजगार के योग्य हैं। इसके अलावा, आईएलउ 2023 की वैश्विक कौशल अंतराल माप और निगरानी रिपोर्ट बताती है कि 47% भारतीय श्रमिक, विशेष रूप से 62% महिलाएं अपनी नौकरियों के लिए अयोग्य हैं। उद्योग द्वारा मांग किए गए कौशल और मौजूदा शैक्षिक और प्रशिक्षण ढांचे के बीच इस असमानता को दूर करने की तत्काल आवश्यकता है। सबसे अधिक युवा आबादी वाले भारत को वैश्विक स्तर पर कार्यबल की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में रणनीतिक लाभ प्राप्त है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भी शिक्षा और रोजगार के बीच चुनौतियों और असमानताओं पर प्रकाश डालता है, देश के भविष्य के कार्यबल को नया आकार देने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता पर जोर देता है। शिक्षा और रोजगार पर वैश्विक मेगाट्रेंड का प्रभाव डिजिटलीकरण, स्वचालन और प्रौद्योगिकियों के एकीकरण सहित वैश्विक मेगाट्रेंड्स शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में इन रुझानों के अनुकूलन की मांग करते हैं। भारत सरकार की योजनाएं, एनईपी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) 2020 और एनपीएसडीई (कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति) शैक्षिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने और भविष्य के प्रयासों के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालाँकि, एनईपी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निवेश, बेहतर बुनियादी ढाँचा, शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रम आवश्यक हैं। जब हम भारत के कौशल परिदृश्य का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। शैक्षिक असमानता और आपूर्ति-मांग के अंतर को पाटने के लिए सरकार और उद्योग द्वारा संचालित कुछ प्रयास शुरू किए गए हैं। हालाँकि, उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता को और बढ़ाने की अनिवार्य आवश्यकता बनी हुई है।

युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता का महत्व भारत के युवाओं में बुनियादी डिजिटल साक्षरता बहुत लंबे समय से गायब है, अधिकांश युवा ईमेल लिखने या संलग्नक के साथ भेजने में असमर्थ हैं। डिजिटल विभाजन को दूर करने और छात्रों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। डेटा प्रोजेक्ट के अनुसार अधिकांश युवा अपने शुरुआती प्रयासों में रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वे अक्सर ऐसी नौकरी भूमिकाओं में पहुंच जाते हैं जो उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि के अनुरूप नहीं होती हैं। जैसे-जैसे देश अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है, डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता बहुत जरूरी है। शिक्षा प्रणाली में डिजिटल कौशल को एकीकृत करने से छात्रों को डिजिटल परिदृश्य में आगे बढ़ने और बढ़ते तकनीकी क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए बुनियादी डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ उपकरणों से लैस किया जाएगा। कौशल विकास में लैंगिक असमानता से निपटना लैंगिक असमानता भी उन मुद्दों में से एक है, जिनसे कौशल और रोजगार क्षेत्र इस समय जूझ रहा है। हालाँकि, पीएमकेवीवाई (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना) और जेएसएस (जन शिक्षण संस्थान) जैसी केंद्रित सरकारी पहलों के कारण राष्ट्र ने कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखी है।

हालाँकि, अयोग्य महिलाओं के कौशल और शिक्षा को बढ़ाने के लिए ऐसे और कार्यक्रमों की आवश्यकता है। सिद्धांत-व्यावहारिक अंतर को पाटना कौशल-आधारित प्रशिक्षण को एकीकृत करनास्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होने से छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने में मदद मिल सकती है। सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच अंतर को पाटना आवश्यक है, और इसे उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। वर्षों से, उद्योग की आवश्यकताओं और शैक्षणिक संस्थानों की पेशकश के बीच एक अंतर रहा है, जिससे कौशल में अंतर पैदा हुआ है और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई है। उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी यह सुनिश्चित कर सकती है कि पाठ्यक्रम उद्योग की मांगों के अनुसार अद्यतन किए जाएं, जिससे नौकरी बाजार के लिए तैयार उम्मीदवार तैयार हों। शिक्षा में नवाचारः प्रौद्योगिकी को अपनाना आज की प्रौद्योगिकी-संचालित दुनिया में, नवाचार शैक्षिक परिदृश्य को बदल रहा है। पारंपरिक कक्षा शिक्षण के साथ डिजिटल उपकरण, एआई और प्रौद्योगिकियों का संयोजन शिक्षाशास्त्र को बढ़ा सकता है और एक आकर्षक सीखने का माहौल बना सकता है, जिससे छात्रों को बदलते रुझानों को समझने और तकनीकी कौशल विकसित करने में सक्षम बनाया जा सकता है। स्कूल अब छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए सह-शैक्षिक विषयों, एआई, रोबोटिक्स और व्यावसायिक प्रशिक्षण की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं।

छात्र रचनात्मक कला, वित्तीय साक्षरता, सार्वजनिक भाषण और एआई, कोडिंग और रोबोटिक्स से संबंधित तकनीकी कौशल में संलग्न हैं, जो 21वीं सदी के कार्यबल के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत के कार्यबल का भविष्यः एकीकृत समाधानों का आह्वान वर्तमान में, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहां इसकी शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता रोजगार और कौशल के भविष्य को समृद्ध कर सकती है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि और उभरती तकनीकी प्रगति के साथ, भारत की शैक्षिक परिदृश्य प्रणाली को कार्यबल के लिए महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करने के लिए अनुकूलित होना चाहिए। शैक्षिक बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास से कार्यबल और कौशल क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत के भविष्य के उन्नत कौशल के लिए प्रौद्योगिकी, उद्योग और शिक्षा का संतुलित एकीकरण अनिवार्य है। यह हमारे देश के युवाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए रोजगार और शिक्षा के बीच अंतर को पाटने में मदद कर सकता है।

दो महीने में जेईई मेन्स-2025 परीक्षा की तैयारी कैसे करें?

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर सत्र 1 और सत्र 2 के लिए जेईई मुख्य परीक्षा तिथि 2025 जारी कर दी है। जेईई मेन सत्र 1 परीक्षा 2025 22 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। सत्र 1 परीक्षा शुरू होने में लगभग दो महीने शेष हैं, इच्छुक उम्मीदवारों को अपनी तैयारी के स्तर में तेजी लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अब समय आ गया है कि उम्मीदवार सभी महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तकों, पुनरीक्षण सामग्री, पिछले वर्षों के पेपर, नमूना और प्रश्न पत्रों के साथ खुद को तैयार कर लें और 360° तैयारी के लिए अपना सब कुछ झोंक दें।

जेईई मेन तैयारी 2025 में मानक एनसीईआरटी किताबें और अन्य लेखकों द्वारा प्रकाशित सामग्री पढ़ने से लेकर परीक्षा से दो महीने पहले तैयारी की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए टेस्ट सीरीज़ लेने तक सब कुछ शामिल है।

जेईई मेन परीक्षा 2025 एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा है जो उम्मीदवारों से तीव्र तार्किक सोच, अवधारणाओं और संबंधित विषयों की स्पष्ट समझ और प्रश्नों के लगातार अभ्यास के साथ-साथ अत्यधिक फोकस की मांग करती है।

जेईई मेन तैयारी 2025

जेईई मेन परीक्षा 2025 की समग्र तैयारी के लिए, छात्रों को मुख्य रूप से तीन विषयों को कवर करना होगा यदि उनका लक्ष्य बी.टेक प्रवेश के लिए है - भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित। प्रत्येक अनुभाग में दो प्रकार के प्रश्न होते हैं - वस्तुनिष्ठ प्रश्न (एमसीक्यू) और ऐसे प्रश्न जिनके लिए उत्तर एक संख्यात्मक मान है। विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले वर्ष के विपरीत, जेईई मेन परीक्षा पैटर्न 2025 को बिना किसी वैकल्पिक प्रश्न के संशोधित किया गया है, जिससे परीक्षा कुछ हद तक कठिन हो गई है।

सत्र 1 की परीक्षा के लिए दो महीने शेष रहते हुए, उम्मीदवार की जेईई मेन की तैयारी उस विषय से शुरू होनी चाहिए जिसमें उनकी पकड़ नहीं है। जिस विषय/अवधारणा/अध्याय का महत्व सबसे अधिक है या परीक्षा में पूछे जाने की अच्छी संभावना है, उसे समझने के लिए शिक्षकों या विशेषज्ञों (ऑफ़लाइन या ऑनलाइन) की मदद लेने की अनुशंसा की जाती है।

जेईई मेन तैयारी युक्तियाँ कोई जादुई छड़ी नहीं हैं जो उच्च स्कोर की गारंटी देंगी। हालाँकि, प्रभावी रणनीतियों को ध्यान में रखने और उनका लगातार पालन करने से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को काफी मदद मिल सकती है। जेईई मेन एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा है, जिसमें आईआईटी और शीर्ष एनआईटी में बी.टेक कार्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए काफी कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है।

जेईई मेन 2025 परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवार निम्नलिखित रणनीतियों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं:

जेईई मेन सिलेबस 2025 को पूरा करें

कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान दें: एक बार जब आप पाठ्यक्रम पूरा कर लें, तो उन विषयों की पहचान करें जहां आप सहज नहीं हैं। सुधार के लिए इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें, साथ ही उन विषयों का अभ्यास भी जारी रखें जिनमें आप पहले से ही मजबूत हैं। इन परिचित क्षेत्रों में कठिन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें।

एक टेस्ट सीरीज़ में नामांकन करें: एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से एक व्यापक टेस्ट सीरीज़ चुनें, और पूरी तैयारी के बाद प्रत्येक परीक्षा को गंभीरता से लें। अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें: प्रत्येक परीक्षण के बाद, अपने प्रदर्शन का आकलन करें और उन विषयों पर ध्यान दें जहां आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं।

स्व-पुनरीक्षण नोट्स बनाएं: ये नोट्स मुख्य बिंदुओं की समीक्षा करना आसान बना देंगे, खासकर परीक्षा से पहले के दिनों में।जेईई मेन तैयारी 2025 के लिए किताबेंआपकी मानक पाठ्यपुस्तक परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

रेटिंग एजेंसियों का भारत पर बढ़ा भरोसा, 2031 तक सात ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी इकोनॉमी

परिवहन विशेष न्यूज

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि भारत की ग्रोथ अगले सात साल के दौरान औसतन 6.7 फीसदी रह सकती है। यह कोरोना महामारी से पहले के दशक की 6.6 प्रतिशत वृद्धि दर के समान है। तब पूंजीगत खर्च और उत्पादकता में बढ़ोतरी का लाभ मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा ब्याज दर और कर्ज से जुड़े नियमों में सख्ती से शहरी मांग प्रभावित होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31 के दौरान भारत की विकास दर औसतन 6.7 प्रतिशत रह सकती है। इस विकास दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था 2031 में सात ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह बात कही है।

क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कोरोना महामारी से पहले के दशक की 6.6 प्रतिशत वृद्धि दर के समान है। तब पूंजीगत खर्च और उत्पादकता में बढ़ोतरी का लाभ मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादा ब्याज दर और कर्ज से जुड़े नियमों में सख्ती से शहरी मांग प्रभावित होने की उम्मीद है। ऐसे में चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

चालू वित्त वर्ष में औसत खुदरा महंगाई 4.5 प्रतिशत रहने की बात कही गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की 5.4 प्रतिशत से कम है। हालांकि, रिपोर्ट में मौसम की स्थिति और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को विकास और महंगाई के अनुमान को लिए जोखिम बताया गया है।

मूडीज ने कहा, अच्छी स्थिति में भारत की इकोनॉमी

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स का कहना है कि मजबूत वृद्धि और महंगाई में नरमी के कारण भारतीय आर्थिकी अच्छी स्थिति में है। रेटिंग एजेंसी ने भारत की विकास दर कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान 7.2 प्रतिशत और 2025 के दौरान 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2025-26 में मूडीज ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान सप्लाई चेन से जुड़ी बाधाओं, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुए ऊर्जा व खाद्य संकट और ज्यादा महंगाई से उबरने में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। अधिकांश जी-20 अर्थव्यवस्थाएं स्थिर विकास का अनुभव करेंगी और नीतिगत सहजता व कमोडिटी कीमतों में नरमी से लाभान्वित होती रहेंगी।

आरबीआई को अच्छी ग्रोथ की उम्मीद

आरबीआई ने तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की ग्रोथ दमदार रहने की उम्मीद जताई है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा ने पिछले महीने के आखिर में कहा था कि मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2024-25 में भारत की जीडीपी 7.2 फीसदी की दर से बढ़ेगी। वहीं, अगले वित्त वर्ष में यह करीब सात प्रतिशत रह सकती है। लेकिन, उसके बाद इस बात की प्रबल संभावना है कि ग्रोथ रेट आठ प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाए।

ऑडिट फर्म डेलाइट इंडिया ने भी कहा था कि मजबूत सरकारी खर्च और अधिक मैन्युफैक्चरिंग निवेश के चलते मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7-7.2 प्रतिशत के बीच रह सकती है।

'पीएम मोदी हफ्ते में 100 घंटे काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं'; 70 घंटे काम वाले बयान पर कायम नारायणमूर्ति

इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायणमूर्ति का कहना है कि देश तभी तरक्की करेगा जब लोग ज्यादा वक्त तक काम करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का भी किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तो हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं। अगर वह इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। नारायणमूर्ति ने जोर दिया कि पीएम की तरह लोगों को भी अधिक काम करना चाहिए।

नई दिल्ली। दिग्गज आईटी फर्म इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के फाउंडर एनआर नारायणमूर्ति सख्त वर्क कल्चर के हिमायती हैं। वह कई बार कह चुके हैं कि लोगों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। इस बात को लेकर उनकी काफी आलोचना भी हो चुकी हैं। हालांकि, कई लोग उनकी बात का समर्थन भी करते हैं।

नारायणमूर्ति ने एक बार फिर अपने 70 घंटे वाले बयान का बचाव किया है। उनका कहना है कि कठिन मेहनत ही भारत को तरक्की की राह पर ले जाएगा।

पीएम नरेंद्र मोदी का भी किया जिक्र

नारायणमूर्ति ने पीएम नरेंद्र मोदी का भी किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं। अगर वह इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। नारायणमूर्ति ने जोर दिया कि पीएम की तरह लोगों को भी अधिक काम करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

जापान-जर्मनी से सीख लेने की सलाह

नारायणूर्ति ने भारतीय नागरिकों को जर्मनी और जापान से सीख लेने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध ने जर्मनी और जापान को बर्बाद करके रख दिया था। लेकिन, दोनों देशों ने कड़ी मेहनत की और फिर से अमीर बन गए। नारायण मूर्ति ने कहा कि भारत को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए और इसी तरह से राष्ट्र का पुनर्निर्माण मुमकिन हो पाएगा। हमें वैसे ही प्रयास करने होंगे, जैसे जर्मनी और जापान के लोगों ने प्रयास किए थे।

बिजनेस स्कूलों से चुनें IAS-IPS

नारायणूर्ति ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि IAS-IPS अधिकारियों को बिजनेस स्कूलों से भी चुना जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के लिए सिर्फ यूपीएससी एग्जाम पर नहीं निर्भर रहना चाहिए। इसके बजाय मैनेजमेंट स्कूलों से सिविल सेवा अधिकारियों के चयन पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी ने इकोनॉमी की रफ्तार देने के मामले में शानदार काम किया है। वह अब इस बात पर गौर कर सकते हैं कि सरकार में क्या हमें प्रशासकों के बजाय मैनेजर्स की अधिक जरूरत है।'

ट्रंप की जीत से अब तक पांच हजार रुपये सस्ता हुआ सोना, क्या आगे भी गिरेगा भाव?

अमेरिका के टैरिफ और ट्रेड वॉर से यूरो और अन्य देशों की करेंसी की वैल्यू घट सकती है। इस स्थिति में उन खरीदारों के लिए सोना खरीदना अधिक महंगा बना देगा जो दूसरे देशों की करेंसी इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि सोने के दाम गिर रहे हैं। अमेरिकी निवेशक भी अब शेयर मार्केट और बिटकॉइन पर बड़ा दांव लगा रहे हैं।

नई दिल्ली। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से अब तक सोना करीब पांच हजार रुपये सस्ता हो चुका है। कमोडिटी मार्केट के जानकारों का कहना है कि मध्यम अवधि में कोई सकारात्मक कारक नहीं दिख रहा है। ऐसे में आने वाले समय में भी सोने के मूल्य में गिरावट जारी रह सकती है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के डेटा के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के दिन यानी छह नवंबर को भारत में सोने का मूल्य 78,566 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 14 नवंबर तक घटकर 73,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इस दौरान सोने के मूल्य में 4,826 रुपये या छह प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है।

और सस्ता होगा सोना

एलकेपी सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के वरिष्ठ शोध विश्लेषक जतिन त्रिवेदी का कहना है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतों में और गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि विक्रेता हावी हैं और निकट अवधि में कोई सकारात्मक संकेत नहीं है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व महंगाई के लक्ष्य के करीब पहुंचने के साथ ही ब्याज दरों में कटौती जारी रखे हुए हैं।

हालांकि, अब वहां महंगाई दर उम्मीद से अधिक होने के कारण इस बात की चिंता बढ़ गई है कि फेडरल रिजर्व आगे कटौती को रोक सकता है। इससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। पीएल ब्रोकिंग के सीईओ संदीप रायचुरा का कहना है कि टैरिफ वॉर होना लगभग तय हो चुका है। इसलिए अमेरिकी डॉलर में काफी तेजी आई है, जो सोने के लिए नकारात्मक कारक है।

क्यों घट रहे सोने के दाम

अमेरिका के टैरिफ और ट्रेड वॉर से यूरो और अन्य देशों की करेंसी की वैल्यू घट सकती है। इस स्थिति में उन खरीदारों के लिए सोना खरीदना अधिक महंगा बना देगा, जो दूसरे देशों की करेंसी इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि सोने के दाम गिर रहे हैं। अमेरिकी निवेशक भी अब शेयर मार्केट और बिटकॉइन पर बड़ा दांव लगा रहे हैं।

साथ ही, ट्रंप के शासनकाल में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में भी आक्रामक तरीके से कटौती नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि ट्रेजरी बॉन्ड पहले के मुकाबले अधिक ब्याज देते रहेंगे और इससे भी सोने की कीमतों को नुकसान पहुंचा सकता है। सोना सीधे तौर पर अपने मालिकों को जीरो डिविडेंड या इनकम देता है। ऐसे में जब बॉन्ड अधिक भुगतान कर रहे होते हैं, तो सोना जाहिर तौर पर कम आकर्षक लग सकता है।

बेशक, सोना अभी भी दुनियाभर में हालात अस्थिर होने पर निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित निवेश रहता है। फिर चाहे बात युद्ध की हो, या फिर राजनीतिक संघर्ष की। वैश्विक अस्थिरता के माहौल में निवेशक अक्सर सोने का रुख करते हैं। मध्य पूर्व, यूक्रेन और अन्य जगहों पर युद्ध अभी भी जारी है। राजनीतिक तनाव अभी भी पहले की तरह ही बना हुआ है। ऐसे में सोना संभवतः कई निवेशकों के पोर्टफोलियो में बना रहेगा।

निर्यातकों की होगी मौज, जल्द शुरू होगा देश का पहला ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब

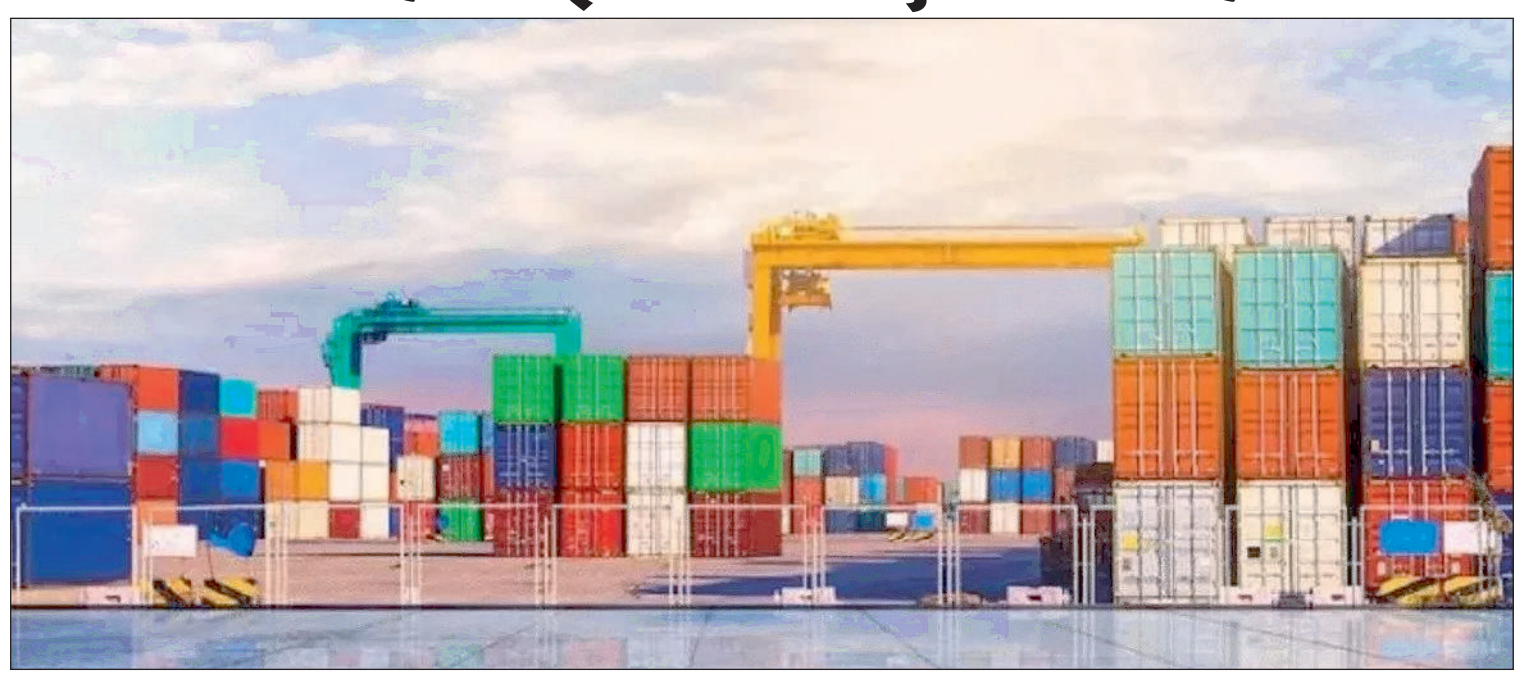

निर्यातक हब में अपने माल को निर्यात के लिए बिल्कुल तैयार मोड में रख सकेंगे और आर्डर मिलते ही उन्हें निर्यात कर दिया जएगा। बजट में देश भर में 10 से अधिक ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाने की घोषणा की गई थी। ताकि छोटे-छोटे शहरों के उद्यमी अपना आइटम विदेश में बेच सके। इससे निर्यातक कस्टम क्लीयरेंस पैकेजिंग और लेबलिंग जैसे काम ऑर्डर मिलने से पहले ही निपटा लेंगे।

नई दिल्ली। अभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए मुख्य रूप देश के भीतर ही कारोबार होता है। ऑनलाइन बाजार के जरिए विदेश से ऑर्डर मिलने पर भी उसे खरीदार तक भेजने में होने वाली परेशानी को देखते हुए ई-कॉमर्स निर्यात बहुत ही सीमित रूप में होता है। लेकिन अब फरवरी से दिल्ली एयरपोर्ट के पास देश का पहला ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब शुरू होने जा रहा है। इससे ई-कॉमर्स निर्यात करना आसान हो जाएगा।

निर्यातकों को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं मिल जाएंगी। एक्सपोर्ट हब में ही कस्टम क्लीयरेंस से लेकर अन्य सभी निर्यात प्रक्रियाएं पूरी करने की तमाम सुविधाएं होंगी। हब में वेयरहाउस भी होगा जहां वे अपना माल रख सकेंगे। पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए भी खास इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं।

तैयार मोड में रहेगा माल

निर्यातक हब में अपने माल को निर्यात के लिए बिल्कुल तैयार मोड में रख सकेंगे और आर्डर मिलते ही उन्हें निर्यात कर दिया जएगा। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में देश भर में 10 से अधिक ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाने की घोषणा की गई थी। ताकि छोटे-छोटे शहरों के छोटे-छोटे उद्यमी अपने आइटम को विदेश में बेच सके।

हब के जरिए निर्यात करने वालों को निर्यात से जुड़े सभी प्रकार के इंसेंटिव भी मिलेंगे। इंसेंटिव पाने के लिए निर्यात की कोई न्यूनतम राशि भी निर्धारित नहीं की गई है।

ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किया था। अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट के पास पहला एक्सपोर्ट हब तैयार हो रहा है। शिपराकेट और कार्गो सर्विस सेंटर नामक दो कंपनियों को इस एक्सपोर्ट हब को तैयार करने का काम दिया गया है।

फरवरी से काम करने लगेगा हब

विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी ने बताया कि फरवरी से यह हब काम करने लगेगा। उन्होंने बताया कि ई-कामर्स एक्सपोर्ट हब की मदद से वर्ष 2030 तक ई-कामर्स निर्यात को 100 अरब डालर तक ले जाने में मदद मिलेगी। इस हब में चौबीस घंटे सातों दिन कस्टम क्लियरेंस की सुविधा होगी। बार-बार चेकिंग या क्लियरेंस नहीं कराना होगा।

उन्होंने कहा कि निर्यात होने वाली वस्तु को निर्यातक खुद भी सील कर सकेंगे। निर्यातकों की मदद के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट होंगे। हब के माध्यम से निर्यात होने वाली वस्तु अगर रिजेक्ट हो जाती है तो उसे विदेश से वापस मंगाने पर कोई आयात शुल्क नहीं देना होगा।

फ्रेट कॉरिडोर से मिल रही उपभोक्ताओं को राहत, चीजों का दाम करने में मिली मदद

विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय रेलवे की आमदनी में डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर ने तीन प्रतिशत से ज्यादा का योगदान दिया है। रेलवे का अनुमान है कि डीएफसी देश के जीडीपी में सीधे लगभग 160 अरब रुपये का योगदान करेगा। माल परिवहन लागत और ढुलाई के समय के घटने से वस्तुओं की कीमतों को आधा प्रतिशत से ज्यादा कम करने में मदद मिली है।

नई दिल्ली। भारत के बड़े इन्फ्रा परियोजना को डीएफसीसी (डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर) ने गति दी है। माल परिवहन में प्रति यूनिट लागत में कमी आने लगी है। अभी देश में प्रतिदिन फ्रेट कारिडोर पर 350 से अधिक मालगाड़ियां दौड़ रही हैं। प्रत्येक एक किमी लंबी मालगाड़ी से सड़क पर दौड़ रहे 72 ट्रकों को हटाने में मदद मिल रही है।

इससे वस्तुओं के परिवहन में आसानी के साथ लाजिस्टिक लागत में भी कटौती होने लगी है। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिल रहा है। सड़कों से वस्तुओं को ढोने में अत्यधिक लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर ही डाल दिया जाता है।

डीएफसी अलग रेल ट्रैक है जिसे मालगाड़ियों के लिए बनाया गया है। अबतक मालगाड़ियों का परिचालन रेल ट्रैक से होता था, जिससे यात्री ट्रेनों के संचालन में विलंब के साथ-साथ अन्य दिक्कतें भी आती थीं। अब डीएफसी पर अत्यधिक क्षमता वाली लंबी रेलगाड़ियां चलाई जा सकती हैं।

फ्रेट कारिडोर से बढ़ी रेलवे की कमाई

विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय रेलवे की आमदनी में डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर ने तीन प्रतिशत से ज्यादा का योगदान दिया है। रेलवे का अनुमान है कि डीएफसी देश के जीडीपी में सीधे लगभग 160 अरब रुपये का योगदान करेगा। माल परिवहन लागत और ढुलाई के समय के घटने से वस्तुओं की कीमतों को आधा प्रतिशत से ज्यादा कम करने में मदद मिली है।

अभी देश की लाजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15 प्रतिशत है। इसे नौ प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य है, जिसमें फ्रेट कोरिडोर की बड़ी भूमिका होगी।

हाल में ही डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना दिवस मनाया है। फ्रेट कारिडोर के जरिए परिवहन का भारत के जीडीपी में 0.8 प्रतिशत का योगदान है। इससे सात राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात एवं राजस्थान एक दूसरे से सीधे जुड़े हैं। कारिडोर के आसपास के

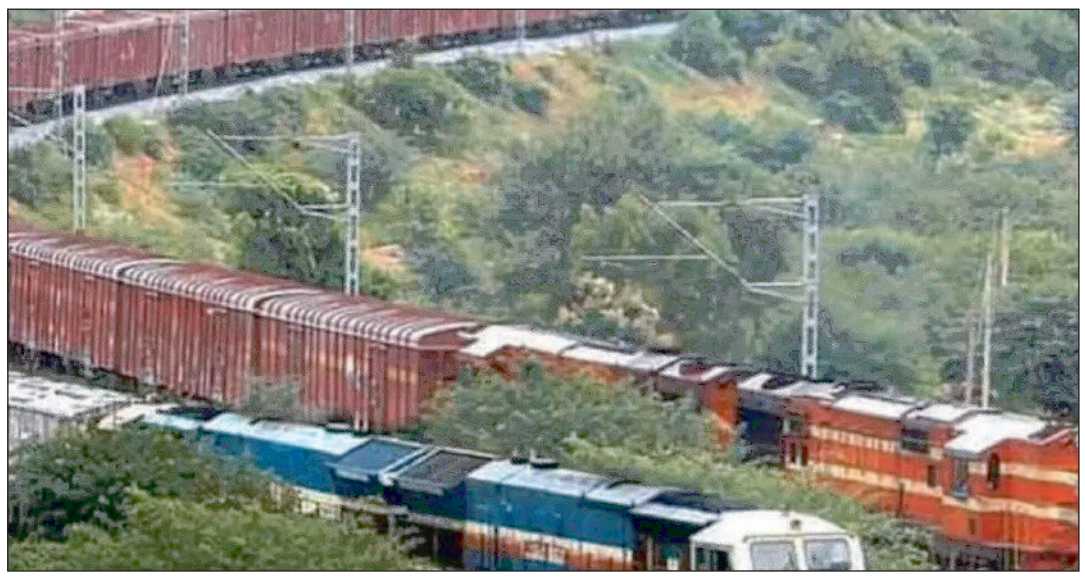

उद्योगों को सीधा लाभ मिल रहा है।

राज्यों के बीच आर्थिक असमानता का फर्क सीमित हो रहा है। देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो रहा है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी आगे बढ़ा रहा है। कोरिडोर पर बन रहे गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल से देश की सप्लाई चेन मजबूत नया अध्याय लिख रही है। आसपास नए औद्योगिक केंद्रों की स्थापना में मदद मिल रही है।

देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है

देश में अभी दो फ्रेट कारिडोर हैं। पूर्वी कारिडोर की लंबाई एक हजार 337 किमी है, जो पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोननगर को जोड़ता है। इसके जरिए कोयला, इंजीनिय¨रग उत्पाद एवं खाद्यान्न को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने में मदद मिलती है। पश्चिमी कारिडोर की लंबाई एक हजार 506 किमी है, जो उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई के जेएनपीटी से जोड़ता है।

इससे सीमेंट, ऑटोमोबाइल एवं जल्द खराब होने वाले उत्पादों को ढोया जाता है। सबसे अधिक आर्थिक लाभ डीएफसी के सबसे करीबी वाले पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ है जहां माल ढुलाई लागत में काफी कमी आई है। दूर वाले क्षेत्रों को भी परिवहन लागत में आई कमी से लाभ पहुंचा है।

कितना मिलेगा लिस्टिंग गेन, क्या शेयरहोल्डर कोटा से कर सकते हैं अप्लाई?

NTPC ग्रीन एनर्जी ने 13 नवंबर को मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट (RHP) दाखिल किया। कंपनियां RHP आईपीओ लाने से ठीक पहले दाखिल करती हैं। इसमें प्राइस बैंड समेत कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं।

नई दिल्ली। निवेशक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। यह एनटीपीसी (NTPC) की सहायक कंपनी है, जो देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। NTPC ग्रीन एनर्जी का आईपीओ अगले हफ्ते 19 से 22 नवंबर के बीच सब्सक्राइब किया जा सकेगा। इस आईपीओ का साइज करीब 10,000 करोड़ रुपये होगा।

क्या शेयरहोल्डर्स कोटा से कर सकेंगे अप्लाई?

NTPC ग्रीन एनर्जी के IPO में रिटेल इन्वेस्टर, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs), क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) और कर्मचारियों के अलावा शेयरहोल्डर्स कोटा भी होगा। इस कोटे के तहत वही इन्वेस्टर्स पैसे लगा सकेंगे, जिनके डीमैट अकाउंट में एनपीटीसी ग्रीन की पैरेंट कंपनी NTPC का शेयर RHP दाखिल करने की तारीख तक रहा होगा।

RHP दाखिल होने की तारीख

NTPC ग्रीन एनर्जी ने 13 नवंबर को मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट (RHP) दाखिल किया। कंपनियां RHP आईपीओ लाने से ठीक पहले दाखिल करती हैं। इसमें प्राइस बैंड समेत कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। RHP दाखिल करने की तारीख तक जिन निवेशकों के पास एनपीटीसी का एक भी शेयर था, वे शेयरहोल्डर कोटे से अप्लाई कर सकते हैं।

NTPC ग्रीन का GMP

प्राइस बैंड तय होने से पहले NTPC ग्रीन एनर्जी का आईपीओ ग्रे मार्केट में गदर काट रहा था। लेकिन, 102 से 108 रुपये का प्राइस बैंड तय होते ही जीएमपी एकदम से क्रैश हो गया। फिलहाल, यह 1.50 रुपये प्रति शेयर पर आ गया है। इसका मतलब कि निवेशकों को 1.39 फीसदी का मामूली लिस्टिंग गेन मिल सकता है।

वाराणसी में मनाया गया देव दीपावली का भव्य पर्व नमो घाट का लोकार्पण, 11 लाख दियों से सजी कशी

रितेश राव

वाराणसी | भारत में प्रत्येक त्योहार देश के हर कोने में मनाया जाता है लेकिन कुछ त्योहार हैं जो विशेषकर किसी राज्य से जुड़े होते हैं. इसी तरह देवताओं की दीपावली यानी देव दीपावली का महत्व विशेषकर भारत की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी से जुड़ा है. इस साल देव दिपावली 15 नवंबर यानी कल शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़े ही धूमधाम और आस्था के साथ मनाई गई. महादेव की नगरी काशी में इस दौरान गंगा किनारे बसे 84 घाटों पर लगभग 11 लाख दीपक जलाए गये. शास्त्रों में मान्यता के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने देवताओं के सभी अधिकारों को उनसे छीनकर स्वर्गलोक पर अपना आधीपत्य जमा लिया था, जिससे परेशान होकर सभी देवता कशी के कोतवाल महादेव के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी. तब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर उसके आंतक से सभी को मुक्ति दिलाई थी. तभी से इस दिन सभी देवतागण देवलोक से काशी में गंगा के घाटों पर आकर भगवान शिव की विजय की खुशी में दिवाली मनाते हैं। इसलिए इस उत्सव को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है.

वाराणसी से सांसद और प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने भी देव दीपावली पर देशवासियों को बधाई दी. देव दीपावली के पावन अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि नमो घाट के फेज-2 का लोकार्पण किया. उन्होंने कहा भारत सनातन की भूमि है, काशी इसका केंद्र है. सनातन में विश्व शांति का संदेश है. सनातन विभाजनकारी ताकतों का विरोध करता है.

इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी मौजूद रहीं. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से यह पर्व अब वैश्विक मंच पर विशेष पहचान बना चुका है. वह घाट जिसे 'नमो घाट' के रूप में जाना जाता है, उसे काशी की जनता 'नरेन्द्र मोदी घाट' कहकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपना आभार प्रकट करती है. उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए आगे कहा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नमामी गंगे परियोजना के तहत किए गए प्रयासों के कारण ही पहले जहां गंगा के जल को स्नान करने योग्य नहीं मना जाता था आज वही गंगा जल आचमन के योग्य हो गया है।

आदिवासी गौरव दिवस मना रहे हैं

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री बिशेश्वर टुडू के रायगढ़ा जिले के दौरे के अवसर पर, उत्कल प्रदेश प्रेस एसोसिएशन द्वारा रायगढ़ा जिले के गुनुपुर में राष्ट्रीय गौरव दिवस के अवसर पर पूर्व केंद्रमंत्री बिस्वेश्वर टुडू के साथ मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय रायगढ़ जिला मजिस्ट्रेट, गुनुपुर विधायक, बिशम कटक की बिधायक उपस्थिति थे ।

विधायक जय नारायण मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद बीजेडी ने बीजेपी पर हमला बोला है

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: संबलपुर के भाजपा विधायक जय नारायण मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद भाजयुमो ने भाजपा पर हमला बोला है। भाजपा विधायक जय नारायण मिश्र का बयान स्वीकार्य नहीं है इसे कहते हैं सत्ता का अहंकार सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं करने का मतलब है कि बीजेपी विधायक कानून से ऊपर हैं । गृह मंत्री, मुख्यमंत्री मोहन माझी ने कहा कि कानून सबके लिए एक जैसा है या उनके स्टाफ राज्यपाल के बेटे के लिए अलग है जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी जब तक सरकार इसका पालन करती है, सभी भाजपा सदस्यों की रक्षा करें। आने वाले दिनों में ओडिशा में कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए या नहीं? पुलिस कानून प्रवर्तन को रोकने में सफल नहीं होगी सरकार और कानून से किसी को डर नहीं रहेगा संदेश यह होगा कि ब्राह्मण लड़का बंदर को मारने का दोषी नहीं है ओड़िशा की जनता यह देखने का इंतजार कर रही है कि मोहन बाबू कितना एक्शन लेंगे ।

सीरवी समाज प्रीमियर लीग-7 का दुसरा चरण कल

हैदराबाद सीरवी फ्रेन्डस्क्लब हैदराबाद द्वारा आयोजित सीरवी समाज प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के 7 वें संस्करण तथा महिला वर्ग के खेलों का दुसरा चरण कल रविवार 17 नवम्बर को सीरवी समाज क्रिकेट ग्राउंड अलियाबाद एवं श्रेष्ठा क्रिकेट ग्राउंड अलियाबाद में आयोजित किया जाएगा। फ्रेन्डस्-क्लब के सुरेश सैंणचा ने बताया कि समाज प्रीमियर लीग-7 का तथा इस प्रतियोगिता के साथ महिला वर्ग के खेलो का बैडमिंटन खेल 17 नवंबर को प्रातः 7.15 को मुख्य प्रायोजक वंडर वॉल पुट्टी की टीम तथा मुख्य अतिथियों के करकमलों द्वारा किया जायेगा। इस बार खेलों को लेकर महिला वर्ग खिलाड़ीयों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। क्रिकेट प्रतियोगिता मे कुल 18 टीमें भाग लेंगी। जिसमें आईजी बिरमगुड़ा ,करमनघाट, एल बी नगर, नागोल वेरिस ,संगारेड्डी, शमशाबाद , मेडचल जिडिमिटला, कापरा किंग्स, रामनगर, ऑल विन 11, बालनगर सिकंदराबाद, आईजी फ्रेंड्स कलब, आईजी गुट्टा 11, हायतनगर, कुकटपल्ली, सैनिकपुरी, टी एम जी टाइटन्स क्रिकेट प्रतियोगिता के साथ साथ महिला वर्ग के बेटमिंटन खेल शामिल होंगे। महिला वर्ग के सभी खेल सिरवी क्रिकेट ग्राउंड अलियाबाद शामिरपेट में आयोजित होंगे। यह प्रतियोगिता सिरवी फ्रेंड्स क्लब हैदराबाद तेलंगाना द्वारा आयोजित की जा रही है। भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर की जाएगी। सभी मैचों का लाईव प्रसारण युट्युब चैनल पर किया जाएगा। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सीरवी फ्रेन्डस्-क्लब के सभी सदस्यों का विशेष सहयोग रहेगा। सभी सीरवी बन्धुओं से निवेदन है इस प्रतियोगिता मे अपना तन-मन-धन से सहयोग करके प्रतियोगिता को सफल बनावे।

गिरफ्तार

अब तकनीक की नहीं थम रही रफ्तार है,
हर कोई आभासी दुनिया में गिरफ्तार है।
हम सबसे पहले देते थे सिनेमा को दोष,
फिर भी रहता था सबको सभी का होश!
यह सब देखकर भी बना रहता था जोश।

अब तकनीक की नहीं थम रही रफ्तार है,
हर कोई आभासी दुनिया में गिरफ्तार है।
अस्सी के दशक में आया था बुद्धू बक्सा,
धीमी ही थी रफ्तार करते बातें रफ्ता-रफ्ता!
समयानुसार हो जाता सब कुछ जो तय था।

अब तकनीक की नहीं थम रही रफ्तार है,
हर कोई आभासी दुनिया में गिरफ्तार है।
जब ओटीटी की दुनिया में हो गया प्रवेश,
अश्लीलता ने पहन लिया हैं नया गणवेश!
गालियों से ही भर गया है ये पूरा परिवेश।

अब तकनीक की नहीं थम रही रफ्तार है,
हर कोई आभासी दुनिया में गिरफ्तार है।
मोबाइल ने ज़बरदस्त हलचल मचाई है,
सोशल मीडिया के द्वारा जगह बनाई हैं!
स्क्रॉल करते ज़िन्दगी में सब गिरफ्तार हैं।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, सूत्रधार व समीक्षक)

इन्दौर में ऐतिहासिक रथ यात्रा में सोने चांदी के रथों पर भगवान की शोभायात्रा सम्पन्न हुई

हरिहर सिंह चौहान

इन्दौर में जैन समाज की रथावर्तन महोत्सव में ऐतिहासिक दिव्य अलौकिक 108 विशेष सोने चांदी के रथों पर शोभायात्रा का शुरुआत गुणायतन तीर्थ भावना योग के प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी संसघ ब्रह्मचारी अशोक भैय्या व ब्रह्माचारी अभय भैय्या और प्रदेश सरकार की और से भाजपा के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रहलाद पटेल जी , मंत्री तुलसीराम सिलावट जी , आर के मार्बल वाले अशोक पटनी जी, व क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला जी पुज्य मुनि श्री के साथ इस शोभायात्रा में शामिल हुए। हमारा शहर ऐसे तो संस्कृति प्रिय शहर है पर इन्दौर के इतिहास में 108 रथों से सुशोभित विशाल रथयात्रा पहली बार शहरवासियों ने देखी। भक्तों की भीड़ सुबह से विजय नगर चौराहे पर लगना शुरू हो गई थी आठ बजते-बजते जनसेलाब विजय नगर एवं एल आई जी पाटनीपुरा भमोरी बड़े बड़े स्वागत मंचों द्वारा भक्तजन व आमजन भी इस ऐतिहासिक दृश्य के गवाह बने। शोभायात्रा में पूरा जैन समाज एकजुटता के साथ इसमें दिखा और अपने अपने जिनालय मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने अपने रथों पर श्री जी को लिए भगवान की जय-

जयकार करते छोती दुपट्टे में बेठे भक्त और सड़कों पर महिला रंग-बिरंगे अलग अलग कलर की साड़ियों में व पुरुष सफेद वस्त्रों में बहुत ही प्रभावी लग रहे थे। वहीं प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए रथों का इन्दौर व उसके आसपास के प्रसिद्ध बेंड बाजे लोक कलाकारों के नृत्य-संगीत संस्कृतिक के विभिन्न रंगों से समाहित यह धर्म प्रभावना समिति का यह रंग सदियों तक याद रहेगा। इन्दौर दिगंबर जैन समाज के ऐतिहासिक सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सात दिनों तक सिद्धों की अराधना में मध्यप्रदेश राजस्थान उत्तरप्रदेश के साथ साथ विदेशों से भी भक्त इसमें शामिल हुए। यह सही बात है इन्दौर के इतिहास में यह विश्व रिकॉर्ड बना जिसमें पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

बदल गया देहात ॥

अपने प्यारे गाँव से, बस है यही सवाल।
बूढ़ा पीपल है कहाँ, कहाँ गई चौपाल॥

रही नहीं चौपाल में, पहले जैसी बात।
नस्लें शहरी हो गई, बदल गया देहात॥

जब से आई गाँव में, ये शहरी सौगात।
मेड़ करे ना खेत से, आपस में अब बात॥

चिट्ठी लाई गाँव से, जब यादों के फूल।
अपनेपन में खो गया, शहर गया मैं भूल॥

शहरी होती जिंदगी, बदल रहा है गाँव।
धरती बंजर हो गई, टिके मशीनी पाँव॥

गलियाँ सभी उदास हैं, पनघट हैं सब मौन।
शहर गए उस गाँव को, वापस लाये कौन॥

बदल गया तकरार में, अपनेपन का गाँव।
उलझ रहे हर आंगना, फूट-कलह के पाँव॥

पत्थर होता गाँव अब, हर पल करे पुकार।
लौटा दो फिर से मुझे, खपरैला आकार॥

खत आया जब गाँव से, ले माँ का सन्देश।
पढ़कर आंखें भर गई, बदल गया वह देश॥

लौटा बरसों बाद मैं, बचपन के उस गाँव।
नहीं रही थी अब जहाँ, बूढ़ी पीपल छाँव॥

—डॉ० सत्यवान 'सौरभ'
तितली है खामोश (दोहा संग्रह)

गाँवों में भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा लागू करने में बाधाएँ

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा एक निरंतर संघर्ष है। लाखों लोग चिकित्सा देखभाल तक सीमित पहुँच के साथ रहते हैं, न केवल स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की अनुपस्थिति का सामना करते हैं, बल्कि पुराने बुनियादी ढांचे के बोझ का भी सामना करते हैं। ये केवल चुनौतियाँ नहीं हैं-ये देरी से होने वाले उपचार और रोकथाम योग्य बीमारियों के पीछे के कारण हैं जो जीवन पर भारी पड़ रहे हैं।

-प्रियंका सौरभ

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली की नींव होती है, खासकर ग्रामीण भारत में, जहाँ 65% से ज़्यादा आबादी रहती है। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएँ देने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचाः ज़्यादातर ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में बिजली, स्वच्छ पानी और उपकरण जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021 के अनुसार, 8% से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवा केंद्र बिना बिजली के काम करते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में डॉक्टरों और नर्सों सहित प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2022 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में डॉक्टरों की 23% कमी है। लंबी दूरी और खराब परिवहन नेटवर्क के कारण दूरदराज के इलाकों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे मरीजों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच प्रभावित होती है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के 40% से ज़्यादा गाँवों में नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र तक पहुँच नहीं है। कम साक्षरता स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता की कमी के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का कम उपयोग होता है। बिहार जैसे राज्यों में कम जागरूकता के कारण टीकाकरण दर कम बनी हुई है। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.3% स्वास्थ्य सेवा पर ख़र्च करता है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023), जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अपर्याप्त है।

पीएचसी में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, बिजली, स्वच्छ पानी और आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करने में निवेश करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करने के लिए अतिरिक्त धन आवंटित कर सकता है। डॉक्टरों और नर्सों के लिए उच्च वेतन, आवास और ग्रामीण भत्ते जैसे प्रोत्साहनों के माध्यम से भर्ती और प्रतिधारण को बढ़ाएँ। तमिलनाडु जैसे राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण सेवा लाभ प्रदान करते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए टेलीमेडिसिन और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों के उपयोग का विस्तार करें। ग्रामीण भारत में टेलीकंसल्टेशन प्रदान करने के लिए ई-संजीवनी का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। मातृ और बाल स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में समुदाय-आधारित जागरूकता कार्यक्रम चलाएँ। ग्रामीण इलाकों में मातृ देखभाल को बढ़ावा देने में आशा कार्यकर्ता प्रभावी रही हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा अनुशंसित सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2.5% तक बढ़ाएँ। थाईलैंड जैसे देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में निरंतर निवेश के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार किया है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में चुनौतियाँ सिर्फ़ मरीज़ों तक सीमित नहीं हैं; वे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के कंधों पर भी भारी बोझ डालती हैं। डॉक्टरों के सामने आने वाली कठोर वास्तविकता हैं-हिंसा, अपर्याप्त आवास और ढहते बुनियादी ढाँचे। ये कारक यहाँ सरकारी अस्पतालों में काम करने के लिए कई लोगों को रोकते हैं। विशेषज्ञों को लाने के प्रयासों के बावजूद, ऐसे पेशेवरों की कमी का मतलब अक्सर यह होता है कि मरीजों को इलाज के लिए ज़िला अस्पतालों में भेजा जाना चाहिए। रकोविड-19 महामारी हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक चेतावनी थी, फिर भी इस क्षेत्र में कोई अतिरिक्त निवेश नहीं हुआ है। सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में, ग्रामीण भारत के लोग, विशेष रूप से पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तानों में रहने वाले लोग, बीमारी का सामना करने पर ख़ुद का ख़्याल रखना जारी रखते हैं-अक्सर बीमारी के गंभीर होने तक देखभाल में देरी करते हैं, बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते हैं या अनौपचारिक, खराब गुणवत्ता वाले प्रदाताओं से देखभाल लेते हैं। जब वे स्वास्थ्य सेवा लेने में सक्षम होते हैं, तब भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें खराब गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिलती है और अक्सर इस प्रक्रिया में वे कर्ज़ में डूब जाते हैं।"

ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुँच बढ़ाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपकरण, टेलीमेडिसिन, अभी भी महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों की उपलब्धता को संरेखित करना, यह सुनिश्चित करना कि रोगियों को इंटरनेट और बिजली जैसे आवश्यक बुनियादी ढाँचे तक पहुँच हो और विशेषज्ञों द्वारा अक्सर सामना की जाने वाली भारी नैदानिक ज़िम्मेदारियों का प्रबंधन करना, ये सभी बाधाएँ हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। एआई टेलीमेडिसिन परामर्शों को अनुकूलित करके, उपलब्धता के आधार पर मामलों को सही केंद्रों तक पहुँचाकर और एक जिला-व्यापी, एआई-सक्षम, हब-एंड-स्पोक मॉडल का समर्थन करके इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है जो नियुक्ति संतुष्टि दरों में सुधार कर सकता। इसके अलावा, एआई की क्षमता ऑडिटिंग और धोखाधड़ी नियंत्रण तंत्र में सुधार तक फैली हुई है, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) जैसे कार्यक्रमों में संसाधन रिसाव को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करके कि संसाधनों का प्रभावी और नैतिक रूप से उपयोग किया जाता है, एआई ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालियों की समग्र अखंडता को मज़बूत करने में मदद कर सकता है। ग्रामीण भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत करना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) प्राप्त करने और ग्रामीण स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए आवश्यक है। केंद्रित बुनियादी ढांचे का विकास, कार्यबल प्रोत्साहन और डिजिटल नवाचार मौजूदा अंतराल को पाट सकते हैं, जिससे सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हो सकती है।

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। **RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**